कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष-61 अंक-7 मुम्बई जून 2017

विशालम स्टील चरखे का अनावरण और हैरिटेज चरखा संग्रहालय का शुभारंभ

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष-61 अंक-7 मुम्बई जून 2017

सम्पादक मंडल

अध्यक्ष

श्रीमती अन्शु सिन्हा

सम्पादक
के. एस. राव

उप सम्पादक
सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खनका

वरिष्ठ कलाकार
संजय एस. सोमदे

कलाकार
चंद्रशेखर पुनवटकर,
दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं
लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
ग्रामोदय,3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),
मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित
टेलिफैक्सः 022-26719465
ई-मेलः jagritikvic@gmail.com वेबसाईटः www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा व्यक्त विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा सम्पादक सहमत हों।

इस अंक में...

समाचार सार 3 से 24

कनॉट प्लेस पर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु आयोग की अविस्मर्णीय पहल.....

पर्यटकों को आकर्षित करता और तिहाड़ की महिलाओं द्वारा बुने गए 'गुंडी' को सामाजिक स्वीकृति दिलाता.....

राष्ट्रपति भवन में हनी मिशन.....

खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा आदित्य बिड़ला फैशन एण्ड रिटेल लिमिटेड के मध्य विपणन अभिसरण.....

खादी बाय रेमंड- रेमंड, खादी कपड़े तथा रेडीमेड परिधानों की तैयार करेगा एक उत्कृष्ट श्रृंखला .....

आयोग द्वारा तिहाड़ जेल में मधुमक्खीपालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत.....

गुजरात के मुख्यमंत्री ने खादी संस्थाओं का दौरा किया .....

समीक्षा बैठक :केन्द्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने ग्रामोदय मुंबई में केवीआईसी की योजनाओं और .....

श्री के. के. जालान, सचिव, एमएसएमई द्वारा खादी बिक्री आउटलेट का दौरा .....

डीएलटीएफसी द्वारा पीएमईजीपी योजना के तहत 59 परियोजनाओं की सिफारिश की.....

आयोग के अध्यक्ष को एल.आय.सी. ने खादी से जुडे कारीगरों के लाभार्थ रु.3,43,800/- का चैक सौपा.....

आयोग के अध्यक्ष द्वारा नव निर्मित खादी भवन, वेजलपुर का उद्घाटन.....

अहमदाबाद में पी.एम.जी.पी. पर एस.एल.बी.सी. की बैठक संपन्न.....

आयोग की 644वीं बैठक का कार्यवृत्त.....29 से 36

लेखः अब अंग्रेज़ों को हुआ खादी से प्यार, हॉलीवुड में भी.....25 से 28

समाचार पत्रों में प्रकाशित खादी ग्रामोद्योग जगत की सुर्खियाँ.....37 से 48

हैरिटेज चरखा संग्रहालय के उदघाटन और विशालतम चरखे के अनावरण के सन्दर्भ में माननीय प्रधान मंत्री का सन्देश पत्र

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
Prime Minister

MESSAGE

I am happy that a Heritage Charkha Museum is being inaugurated and a Large Steel Charkha is being unveiled at Connaught Place, New Delhi by the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) in association with the New Delhi Municipal Council (NDMC). It is also heartening to see that Charkhas are being distributed to Khadi artisans from seven states on this occasion.

As Mahatma Gandhi himself believed, the Charkha is a symbol of our Swaraj and Self-reliance. The museum and the monument for the Charkha in the National Capital will be a proud tribute to the Charkha's historic importance in our nation.

I am sure this endeavour will help everyone to appreciate the significance of the Khadi Industry in our country and make Khadi more popular. This will economically empower the lives of several weavers associated with the Khadi industry.

I congratulate KVIC and NDMC on this endeavour and wish them all the success.

(Narendra Modi)

New Delhi
31 March, 2017

Shri V.K Saxena
Chairman
Khadi and Village Industries Commission
New Delhi

कनॉट प्लेस पर पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु आयोग की अविस्मर्णीय पहल

नई दिल्ली, 23 मई, 2017: पर्यटन के साथ चरखे को जोड़ने की प्रथम पहल को देखने के लिए एकत्रित हुए सैकड़ों लोगों की उत्साह व उल्लास देखते ही बन रहा था, जब नई दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस, पालिका बाजार में भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने विशाल इस्पात (स्टील) चरखे का अनावरण और हैरिटेज चरखा संग्रहालय का उदघाटन किया – जिसमें 14 विंटेज चरखे शामिल हैं, जो सैकड़ों लोग के लिए अत्यंत अद्भुत और अविस्मर्णीय पल था। वहां अप्रत्याशित बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट के बावजूद भी उपस्थित लोग इस सबसे बड़े इस्पात चरखे का अनावरण और हैरिटेज चरखा संग्रहालय के उद्घाटन समारोह के ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने।

अपने व्यस्त कार्यक्रम और प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद भी जिन गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी उसमें शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह; केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र, केन्द्रीय संस्कृति मंत्री डॉ. महेश शर्मा; केन्द्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री श्री विजय गोयल, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री; श्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी, शहरी विकास राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह; संसद सदस्य श्रीमती मीनाक्षी लेखी; संसद सदस्य श्री सतपाल सिंह,

भाजपा नेता श्री करण सिंह तंवर इसके अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के सचिव श्री के. के. जालान; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के संयुक्त सचिव श्री बी. एच. अनिल कुमार; एनडीएमसी के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार; आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अन्शु सिन्हा और वित्तीय सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश, के साथ-साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा एनडीएमसी के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा एनडीएमसी के संयुक्त सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की।

अपने उद्बोधन में आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि चरखा आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक स्वतंत्रता की कहानी लिखेगा। नई दिल्ली नगर परिषद परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष श्री नरेश कुमार ने कहा कि यह 'चरखा' न केवल नई दिल्ली क्षेत्र में बल्कि देश के समृद्धि का एक प्रतीक होगा और हमारे समग्र संस्कृति की समृद्ध

विरासत को संरक्षित करने में सूत्रपात की भूमिका निभाएगा। "चरखा केवल स्वदेशी द्वारा सादगी और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है बल्कि यह शांति और सामंजस्य का प्रतीक भी है, इसलिए यह 'मेक इन इंडिया' के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा"। उन्होंने कहा कि "एनडीएमसी इस भारतीय विरासत को बनाये रखने के लिए चरखे और हेरिटेज संग्रहालय के संरक्षण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। निगम परिषद, नई दिल्ली क्षेत्र को बदलने के लिए आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी माध्यम से कुशल, प्रभावी कठिन परिश्रम कर रही है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि यह

चरखा अज्ञात उन सैनिकों और अज्ञात ग्रामीण जनता का स्मारक है, जिन्होंने आत्म निर्भरता के लिए राष्ट्र पिता द्वारा दिखाये परिश्रम में गरिमामयी मार्ग का अनुसरण किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को चरखों के मालिकों द्वारा उपहार में दिए गए 50 से100 वर्ष पुराने इन चरखों को प्रदर्शित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नई दिल्ली नगर निगम की सहयोग से इस हैरिटेज चरखा संग्रहालय की स्थापना की है । उन्होंने आगे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लुधियाना में 8 अक्टूबर 2016 को एक कार्यक्रम के दौरान चलाये गए चरखे को भी जनसामान्य के देखने के लिए स्थायी रूप से इस संग्रहालय में रखा गया है। "राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में स्थित यह विदेशी पर्यटकों को निश्चित रूप से लुभायेगा। महात्मा गांधी की ओजमयी

संगमरमरी प्रतिमा और इस्पात चरखा बाबा खड़क सिंह मार्ग के चारों ओर से दिखाई देगा।"

इस पहल का प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष को भेजे अपने विशेष संदेश में अभिवादन करते हुए कहा: **"महात्मा गांधीजी का स्वयं का मानना था कि चरखा हमारे स्वराज और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। राष्ट्रीय राजधानी में चरखा स्मारक व संग्रहालय हमारे देश में चरखा के ऐतिहासिक महत्व के लिए एक गौरवपूर्ण श्रद्धांजलि होगा। यह खादी उद्योग से जुड़े बुनकरों के जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य करेगा। "**

2.5 टन का विशाल स्टील चरखा उच्च गुणवत्ता वाली क्रोमियम निकल स्टेनलेस स्टील से बना है और जंग प्रतिरोधी, उष्णता प्रतिरोधी है। इस 12 फीट ऊंचे व 25 फीट लंबे कताई चरखे को बनाने का कार्य गुजरात में साबरमती आश्रम के निकट, खादी और ग्रामोद्योग की इकाई, खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति के माध्यम से केवीआईसी द्वारा किया गया है। चरखे के लिए उच्च गुणवत्ता वाला स्टेनलेस स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) द्वारा दान किया गया है।

इस अवसर पर विभिन्न राज्यों की महिला कत्तिनों को करीब 70 लाख रुपये की

लागत के 500 नए मॉडल आठ-तकुआ चरखे दान स्वरूप प्रदान किये गए,इसके अलावा तिहाड़ जेल की10 महिला कैदियों द्वारा जीवंत चरखा प्रदर्शन भी किया गया।

पर्यटकों को आकर्षित करता और तिहाड़ की महिलाओं द्वारा बुने गए 'गुंडी' को सामाजिक स्वीकृति दिलाता- चरखा संग्रहालय

नई दिल्ली, 23 मई, 2017: सोमवार को, लगभग 40 वर्षीय ममता रानी, कनॉट प्लेस के पालिका पार्क में तिरंगा गुंडी (खादी सूत से बनी माला) के लिए अपनी बारी के इंतजार में एक लंबी कतार में खड़ी थी। "यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि यह इस हैरिटेज चरखा संग्रहालय में प्रवेश करने के लिए टिकट है।" इस प्रवेश टिकट को पाने के बाद उसने बताया, "यह तिहाड़ की उन महिला कैदियों द्वारा महात्मा गांधी के सम्मान का प्रतीक है - जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर और अपने भविष्य को संवार रही हैं और वह भी - आत्मनिर्भरता के उपकरण चरखे के साथ-जिसे बापू द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपयोग में लाया गया था"।

नई दिल्ली नगर निगम (एन.डी.एम.सी.) के सहयोग से खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित हैरिटेज चरखा संग्रहालय जो महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित और समर्थित आदर्श विचारों का एक समागम है। इसका उद्देश्य न केवल चरखा के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि तिहाड़ जेल के उन 10 महिला कैदियों को सामाजिक स्वीकृति देता है-जिन्होंने 'तीन रंग की गुंडी' की बुनाई की जिसका उपयोग 'प्रवेश टिकट' के रूप में पर्यटकों द्वारा किया जा रहा है | इसे देखने के लिए सोमवार (सप्ताह के पहले कामकाजी दिन) को ही 1,522 और मंगलवार को अपराहन 4 बजे तक 1,200 से अधिक लोग उपस्थित हुए।

इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया, दिलचस्प बात यह है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने संग्रहालय के नाम के लिए गंगा बेन महिला के नाम पर विचार किया था, जिन्होंने गांधी के लिए चरखा की खोज की थी। "इस संबंध में बड़ी चर्चा करने के पश्चात्, हमने अंतत: कुटीर का नाम 'गंगा बेन कुटीर' के रूप में चुना।" आयोग के अध्यक्ष ने कहा, "गांधी जी और गंगा बेन के लिए यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी ।" जेल अधिकारियों की देखरेख में महिला कैदी सुबह 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक बुनाई करती हैं । यह उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का एक तरीका है क्योंकि वे बुनाई के माध्यम से प्रति दिन 200 रुपये अर्जित करती हैं। यह निश्चित रूप से इन कैदियों को समाज में अधिक स्वीकार्य बनने में सहायक होगा, क्योंकि एक समय जब उन्हें जेल छोड़ना पड़ेगा |

इस दौरान हेरिटेज चरखा संग्रहालय के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 20 रुपये प्रवेश शुल्क ट्रायल के तौर पर तय किया गया है। एनडीएमसी के अधिकारियों में से एक ने बताया, "एक बार जब परीक्षण की पेशकश समाप्त हो जाएगी तो प्रवेश शुल्क 12 साल से कम के बच्चों के लिए 20 रुपये और वयस्कों के लिए 50 रुपये हो जाएगा।"

उल्लेखनीय है कि, नई दिल्ली नगर निगम के सहयोग से खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हैरिटेज चरखा संग्रहालय स्थापित किया है। जिसमें 50 से 100 वर्ष पुराने चरखों को प्रदर्शित किया गया है, जो इन चरखों के मालिकों द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग को उपहार स्वरूप दिए गये हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लुधियाना में 8 अक्टूबर 2016 को एक कार्यक्रम के दौरान चलाये गए चरखे को भी जनसामान्य के देखने के लिए स्थायी रूप से इस संग्रहालय में रखा गया है।

कार्यक्रम की झलकियां:

दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित पालिका बाज़ार में 14 विंटेज चरखे के साथ 12 फीट ऊंचे व 25 फीट लंबे विशाल स्टील चरखे का अनावरण। 2.5 टन का विशाल स्टील चरखा उच्च गुणवत्ता वाली क्रोमियम निकल स्टेनलेस स्टील से बना और जंग प्रतिरोधी, उष्णता प्रतिरोधी है। चरखे के लिए उच्च गुणवत्ता वाला स्टेनलेस स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) द्वारा दान किया गया है।

2. नई दिल्ली नगर निगम (एन.डी.एम.सी.) के सहयोग से खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित हैरिटेज चरखा संग्रहालय का उद्घाटन, जो महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित और समर्थित आदर्श विचारों का एक समागम है।

हैरिटेज चरखा संग्रहालय जिसमें 50 से 100 वर्ष पुराने चरखों को प्रदर्शित किया गया है, जो इन चरखों के मालिकों द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग को उपहार स्वरूप दिए गये हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लुधियाना में 8 अक्टूबर 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चलाये गए चरखे को जनसामान्य के देखने के लिए स्थायी रूप से इस संग्रहालय में रखा गया है।

3. विभिन्न राज्यों की महिला कत्तिनों को करीब 70 लाख रुपये की लागत से 500 नए मॉडल आठ-तकुआ चरखे उपहार स्वरूप दिए गए।

4. तिहाड़ जेल की 10 महिला कैदियों द्वारा जीवंत चरखा प्रदर्शन भी किया गया। जिससे तिहाड़ जेल के उन महिला कैदियों को सामाजिक स्वीकृति की भावना भी मिलेगी।

राष्ट्रपति भवन में हनी मिशन

आयोग द्वारा राष्ट्रपति भवन में मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण की शुरूआत।

देश की राजधानी में 5,000 मधुमक्खी बॉक्स स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर आयोग ने राष्ट्रपति भवन परिसर में 500 बी-बॉक्स की स्थापना की।

नई दिल्ली: दुनिया में सर एडविन लैंडसेर लुटियंस का सबसे बड़े सभापति भवन- राष्ट्रपति भवन - ने अब प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वप्न परियोजना (ड्रीम प्रोजेक्ट) 'स्वीट क्रांति' (मधु क्रांति) लाने की ओर ध्यान आकर्षित किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने आमों के रसीले पेड़, भारतीय ब्लैकबेरी (जामुन), नीम और सहजन सहित प्रचुर मात्रा में वनस्पतियों और जीवों के साथ अमृत-उत्पादक उद्यान के बारे में जानकारी लेकर, मंगलवार को राष्ट्रपति भवन परिसर में राष्ट्रपति इस्टेट के बगीचे हेतु एपिकल्चर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की। इस पाठ्यक्रम में लगभग 50 मालियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए, आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने मालियों को मधुमक्खी पालन के व्यापक क्षेत्र तथा मधुमक्खी वाटिका और मधुमक्खीपालन, पेड़-पौधे एंव जीव-जंतुओं के महत्व तथा इनकी देखरेख के बारे में अवगत कराया तथा महत्वपूर्ण सुझाव दिए| "प्रशिक्षण के पश्चात् आयोग ने निर्णय लिया कि आयोग, राष्ट्रपति भवन के परिसर में स्थित बगीचों में विभिन्न चरणों में 500 से ज्यादा मधुमक्खी बॉक्स स्थापित करेंगा| इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 12,500 किलोग्राम से अधिक उच्च गुणवत्तायुक्त शहद और 300 किलोग्राम बेहतर गुणवत्तायुक्त मोम उत्पादित करने के साथ-साथ, राष्ट्रपति भवन संपदा के आसपास वनस्पतियों और जीवों को बढ़ावा दिया जायेगा तथा फसल की पैदावार में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी। "यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग एंव नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दिल्ली के विभिन्न आरक्षित वन क्षेत्रों के अलावा, दिल्ली के विभिन्न बागानों में इस वर्ष 5000 मधुमक्खी बॉक्स लगाने का निर्णय लिया है, जिसमें लोधी गार्डन, टालकटोरा गार्डन और नेहरू पार्क भी शामिल हैं। एनडीएमसी अधिकारियों ने भी हमारे मिशन में अपने समर्थन का हाथ बढ़ाया है।"

श्री सक्सेना ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मधुमक्खी पालन विशेषज्ञों ने शहद मधुमक्खी प्रजातियों, कॉलोनी संगठन, श्रम विभाजन और मधु मक्खियों के जीवन चक्र, विभिन्न मौसमों के दौरान शहद मधुमक्खी कालोनियों के प्रबंधन पर अनुसन्धान किया है। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि माली, "मधुमक्खी कालोनियों की जांच करने, मधुमक्खी दुश्मनों और मधुमक्खियों से सम्बंधित रोगों, शहद निकासी और मोम शुद्धिकरण करने और विभिन्न ऋतुओं जैसे वसंत, ग्रीष्म, मॉनसून और सर्दियों के मौसमों में मधुमक्खी कालोनियों (उपनिवेशों) का प्रबंधन करने और प्रबंधन के साथ शहद उपनिवेशों की जाँच करने हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य- हमारे प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए 'स्वीट क्रांति' के आह्वान के बाद, प्रत्येक परिवार और प्रत्येक को उनके दैनिक जीवन के उपभोग हेतु स्वीट नेक्टर उपलब्ध कराना है। शहद, रोगप्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने और रक्त को शुद्ध करने में सहायक है | इसका एक औषधीय गुण है, यह हृदय रोगों और कैंसर जैसे प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं से शरीर को बचाता है।

जैसा कि ज्ञात है कि विगत माह में राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में, आयोग के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के सचिव को सुझाव दिया था कि 500 मधुमक्खी बक्से की स्थापना करके वहां से 'हनी मिशन' लॉन्च करें, जिसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दी। इससे पहले, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 9 मई को तिहाड़ जेल क्र. 5 के कैदियों के लिए पांच दिवसीय मधुमक्खी पालन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था।

इस अवसर पर राष्ट्रपति की सचिव ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में नए वृक्षों के रोपण और ट्यूलिप आदि जैसे फूलों की दुर्लभ किस्मों की शुरुआत सहित बागवानी के क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन में बहुत सी नई पहलें की गई हैं। क्षेत्र की भरपूर वनस्पति को देखते हुए राष्ट्रपति भवन में निर्मित मधु उत्तम गुणवत्ता का होगा। प्रशिक्षण के बाद खादी ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रपति भवन परिसर में विभिन्न चरणों में 500 मधुमक्खी बक्से रखेगा। इसके अलावा, मधुमक्खी पालन से राष्ट्रपति संपदा में और उसके आसपास वनस्पति और जीवों में वृद्धि तथा फसल के कम से कम 25 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा आदित्य बिड़ला फैशन एण्ड रिटेल लिमिटेड के मध्य विपणन अभिसरण

नई दिल्ली, 23 मई, 2017: खादी इंडिया के फैशन पावर हाउस को सशक्त बनाने और उसमें नयी ऊर्जा के संचार हेतु आदित्य बिड़ला फैशन व रिटेल लिमिटेड एंव खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दो प्रतिष्ठित भारतीय ब्रांडों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए आज एक रणनीतिक सहभागिता की घोषणा की। यह पहल, माननीय प्रधान मंत्री के 'खादी फ़ॉर फ़ैशन' और हाथ बुने वस्त्र को बढ़ावा देने के विजन के अनुरूप है । खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अन्शु सिन्हा और आदित्य बिड़ला फैशन और रिटेल लिमिटेड, बिजनेस मुख्य श्री आशीष दीक्षित ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थिति में समझौता दस्तावेज का आदान-प्रदान किया । इस रणनीतिक साझेदारी के एक हिस्से के रूप में, आदित्य बिड़ला फैशन और रिटेल लिमिटेड के फैशन ब्रांड पोर्टफोलियो के अग्रणी मेन्सवियर ब्रांड पीटर इंग्लैंड, प्रतिष्ठित ब्रांडों में से एक होगा, जिसे 'खादी बाय पीटर इंग्लैंड' के रूप में एक विशेष ब्रांडेड उत्पाद लाइन का विकास किया जाएगा।

इस पार्टनरशिप (साझेदारी) पर बोलते हुए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा "खादी, भारतीय विरासत का वस्त्र, जो महात्मा गांधी के द्वारा खोजी गई और प्रचारित की गई, जो समय के साथ और बढ़ रही है तथा बहुत कम पूंजी निवेश पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रमुख रोजगार प्रदाता बन गई है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खादी खरीदने और ग्रामीण कारीगरों को समर्थन देने के लिए देशवासियों से नियमित रूप से अपील करके खादी कार्यक्रम को प्रमुख रूप में बढ़ावा दिया है। इससे खादी की

मांग में वृद्धि हुई है और मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री वर्ष 2016-17 के दौरान 50,000 करोड़ रुपये पार कर गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग-आदित्य बिड़ला फ़ैशन एंड रिटेल लिमिटेड के बीच यह कन्वर्जेन्स खादी को ब्रांडेड कपड़ों के बाजार में एक बड़े पैमाने पर लाने की एक प्रमुख पहल है, जो युवा वर्ग और खासकर हाई इंड बाज़ार की मांग जैसे बेहतर डिजाइन, रंग और शैली को पूरा करेगा। यह कन्वर्जेन्स खादी कारीगरों को लगभग **2** लाख व्यक्ति घंटे का कार्यदिवस प्रदान करेगा और खादी के रेडीमेड वस्त्रों में निश्चित रूप से आवश्यक पेशेवर इनपुट लाएगा।"

इस सहभागिता पर मत प्रकट करते हुए, आदित्य बिड़ला फैशन और रिटेल के बिजनेस हेड श्री आशीष दीक्षित ने कहा, "खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ हमारी भागीदारी, नवीकरण और टिकाऊ फैशन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 'राष्ट्र के वस्त्र' के रूप में जानी जाने वाली खादी-आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो एक बहुमुखी वस्त्र है, यह पर्यावरणनुकूल है और सादगी के साथ इसमें एक उच्च-फैशन अपील है । प्रमाणिक भारतीय उत्पाद भारतीय उपभोक्ताओं के साथ दृढ़तापूर्वक प्रतिध्वनित होते हैं और आज हाथ निर्मित वस्त्रों की मांग बढ़ती जा रही है, जो अपने वास्तविकता से जुडी है और यह अपने सादगी और प्रचलन के बारे में बताती है। आयोग के साथ हमारी पार्टनरशिप (साझेदारी) करने का उद्देश्य - इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को हाथ-बुने वस्त्र और समृद्ध भारतीय विरासत से अवगत कराना है।"

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अन्शु सिन्हा ने इस रणनीतिक पहल के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि "आयोग, खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई नई विपणन पहल कर रहा है। इसके तहत आयोग ने पहले ही कॉरपोरेट्स, पीएसयू और सरकारी विभागों जैसे ओएनजीसी, एयर इंडिया, स्वास्थ्य मंत्रालय, जेके सीमेंट इत्यादि से थोक ऑर्डर प्राप्त किये हैं, जो खादी के लिए बाजार का विकास करेंगे और उत्पादों में डिजाइन विकास करने सम्बंधित क्षेत्र में पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रेमंड लिमिटेड एवं आदित्य बिड़ला फैशन और रिटेल लि. जैसे बड़े बाजार दिगज्जों के साथ कन्वर्जेन्स विकसित किए हैं। यह दोनों संगठनों के लिए एक सफ़ल प्रस्ताव होगा और जो खादी कारीगरों को स्थायी रोजगार प्रदान करेगा। "

जैसाकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिनियम के तहत अवधारणा है कि आयोग का कार्य- खादी अथवा ग्रामोद्योगी उत्पादों या हस्तशिल्पों उत्पादों

की बिक्री और विपणन को बढ़ावा देने और पीपीपी(मोड) के माध्यम से स्थापित विपणन एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करना है। आयोग का अधिनियम, इस पहल को अनुमति देता है। इस कन्वर्जेन्स के तहत पीटर इंग्लैंड, सूती और रेशम मसलीन की प्राथमिक खरीद के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए खादी और खादी उत्पादों की गारंटीकृत न्यूनतम खरीद करने के लिए सहमत हो गया है। यह साझेदारी न केवल खादी कारीगरों और संस्थाओं को एक निश्चित बाजार प्रदान करेगी बल्कि खादी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों की दक्षता में वृद्धि प्रदान करेगी तथा इससे वस्त्र और सूत के डिजाइन को उन्नत करने में सहायता होगी और स्थायी रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

'खादी वाय पीटर इंग्लैंड' भारतीय लोकाचारों

और नवीनतम विचारधाराओं का एक समिश्रण हैं, खादी को एक फैशनेबल वस्त्र के रूप में पेश करना सुनिश्चित है। इस रणनीतिक साझेदारी के एक हिस्से के रूप में, पीटर इंग्लैंड भी तकनीकी विशेषज्ञों को उपलब्ध कराने के साथ ही पूरे देश में खादी विनिर्माण समूहों में डिजाइन इंटरवेंशन (हस्तक्षेप) करेगा। इसके अतिरिक्त, पीटर इंग्लैंड ओटीसी बिक्री के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विभागीय बिक्री केन्द्रों के माध्यम से अपने कपड़ों के ब्रांडों के लिए क्राफ्टिंग कपड़ों के सभी भारतीय खादी किस्मों की खरीद करेगा। इसके साथ ही, खादी लोगो को विजुअल मार्केटिंग के माध्यम से पीटर इंग्लैंड स्टोर में प्रदर्शित किया जाएगा, जहां पर खादी उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। वर्तमान में, खादी को खादी ग्रामोद्योग भवन के बिक्री केन्द्रों और खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा खादी और ग्रामोद्योग मंडल द्वारा वित्तपोषित संस्थानों द्वारा संचालित बिक्री केन्द्रों के माध्यम से विपणन किया जा रहा है।

'खादी वाय पीटर इंग्लैंड' पूरे देश के पीटर इंग्लैंड के स्टोरों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बिक्री केन्द्रों, प्रमुख ई-कॉमर्स पोर्टल में उपलब्ध होगी | पीटर इंग्लैंड ब्रांड की बिक्री करने के लिए करीब 700 रिटेल बिक्री केंद्र हैं और ये सभी नए खादी रेंज के विपणन के लिए शामिल होंगे।

KHADI by Raymond - भारत का पहला ब्रांडेड खादी लेबल

रेमंड, खादी कपड़े तथा रेडीमेड परिधानों की तैयार करेगा एक उत्कृष्ट श्रृंखला

मुंबई, 18 मई, 2017: "गांधीजी और मोदीजी का वैश्विक बाजार में खादी को बढावा देने का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हम उद्यमिता के मार्ग को स्वीकार नहीं करेंगे"-यह बात केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने रेमंड लिमिटेड समूह द्वारा मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में 'खादी बाय रेमंड इंडिया' के पहले ब्रांडेड खादी लेबल के औपचारिक लोकार्पण के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि "रेमंड के साथ सार्वजनिक निजी साझेदारी से उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बाजार संबंधों को सुनिश्चित किया जा सकेगा एवं इससे मांग में वृद्धि होगी और कारीगर भी लाभान्वित होंगे।

उन्होंने आगे कहा कि हाथ बुना, हाथ कता "कार्बन रहित" खादी वस्त्र- ग्रीष्म में शीतलता और शीत ऋतु में गर्मी प्रदान करता है और इसमें प्रकृतिनुकूल और त्वचानुकूल होने का एक अनोखा गुण है। श्री सिंह ने यह भी जानकारी प्रदान की कि "सौरचालित कताई चरखा, भावी पांच वर्षों में सम्पूर्ण राष्ट्र में पांच करोड़ लोगों को रोजगार

प्रदान करने में सक्षम होगा । सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री ने आगे कहा कि सौर चरखे से हरित आर्गेनिक खादी सूत बनता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। इस चरखे से अधिक से अधिक रोजगार का सृजन होगा और सूत की लागत कम होने से खादी प्रतिस्पर्धात्मक बनेगी।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा, "यह एक ऐतिहासिक क्षण है और खादी के साथ बुद्धिजीवियों का एक संयोजन है, जो उत्कृष्ट खादी परिधानों के लिए लाभदायी है। इस पहल से खादी बाजार (मार्केट) के लिए नए मार्ग खुलेंगे और इससे हमारे देश के ग्रामीण कारीगरों के जरूरतों की पूर्ति होगी एवं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आवाहन से सभी भारतीय खादी को अधिक से अधिक उपयोग में लाएगें । उन्होंने आगे कहा कि "खादी बाय रेमंड" खादी सूत के मिश्रणों की एक अति सुंदर श्रेणी होगी और भारतीय संस्कृति के साथ रेमंड की समृद्ध विरासत को कायम रखेगी और जो आज के विवेकाशील भारतीय ग्राहक के साथ तालमेल बैठाती है। इस समझौते से कारीगरों के लिए तीन लाख मानव घंटे का रोजगार सृजन होगा। यह खादी क्षेत्र में सफलता का एक नया अध्याय भी जोड़ेगा|

इस अवसर पर बोलते हुए रेमंड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री गौतम हरि सिंघानिया, ने कहा; "यह वास्तव में खादी के लिए गर्व का क्षण है - खादी हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो के एक भाग के रूप में हमारे राष्ट्र का वस्त्र है| हमारा उद्देश-नवीनतम डिजाइन प्रवृत्तियों को स्वीकार करना और उसकी गुणवत्ता बढ़ाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा ध्येय रेमंड खादी को एक पसंदीदा खादी वस्त्र के रूप में परिवर्तित करना है और माननीय प्रधान मंत्री जी के विजन "खादी फॉर फैशन" को बढ़ावा देना और "मेक

इन इंडिया" की पहल के लिए हमारी प्रतिबद्धता को बहाल करना है।

इस अवसर पर सम्मानीय अतिथि के रूप में उपस्थित महात्मा गांधी की पोती सुश्री सुमित्रा कुलकर्णी गांधी ने खादी का पुनः स्मरण किया और इस स्वदेशी वस्त्र

को एक मिशन के साथ स्वीकार करने की अपील की जिससे कातिनों, बुनकरों और उत्पादकों की मदद हो सके। उन्होंने आशा जतायी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग एंव रेमंड के मध्य यह साझेदारी निश्चित रूप से इस उद्देश्य और एक मकसद के रूप में कार्य करेगी।

यह भव्य समारोह में अन्य माननीय अतिथियों की उपस्थिति का भी साक्षी बना। कार्यक्रम में माननीय मंत्री (उद्योग एवं खनन), महाराष्ट्र सरकार श्री सुभाष देसाई, माननीय मंत्री (शिक्षा), गुजरात सरकार श्री भूपेंद्र सिन्हा चुडासमा, खादी और ग्रामोद्योग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री अन्शु सिन्हा और वित्तीय सलाहकार सुश्री उषा सुरेश के अतिरिक्त अन्य लोग ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई।

फ़ैशन शो में कई मॉडलों ने रेमंड खादी से बनाए गये भव्य संग्रह को प्रदर्शित किया, जिसमें प्रत्येक अवसर के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय वस्त्र, आरामदायक पोशाक, स्मार्ट फोर्मल्स और एथनिक परिधान शामिल थे।

प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन और फिल्म अभिनेता कबीर बेदी और भारतीय फिल्म अभिनेत्री तन्निष्ठ चटर्जी

ने शाम को एक साथ भारत की स्वतंत्रता और खादी को आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में स्मरण करते हुए पुरानी यादों का पुनः स्मरण किया|

यह पहल खादी मार्क विनियम अधिनियम के तहत संकल्पित है और यह, ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों या खादी या खादी उत्पादों तथा हस्तशिल्पों की बिक्री और विपणन को बढ़ावा देने और पीपीपी मोड के माध्यम से विपणन एजेंसियों के साथ लिंक स्थापित करने हेतु

रेमंड को अनुमति देता है। इस कनवर्जेन्स के तहत रेमंड ने 5 साल की अवधि के लिए खादी और खादी उत्पादों के साथ-साथ मसलिन खादी, सूती खादी, ऊनी मिश्रित और रेशम खादी के प्राथमिक न्यूनतम खरीद के लिए सहमति जताई है। यह सामरिक साझेदारी

(पार्टनरशिप), पूरे देश में कई रेमंड बिक्री केन्द्रों के साथ-साथ चुनित अंतरराष्ट्रीय बाजारों के माध्यम से खादी के लिए नए द्वार खोलेगा।

पहल के एक भाग के रूप में रेमंड, सभी भारतीय खादी के विभिन्न किस्मों की खरीद करेगा और अंतिम परिष्करण की प्रक्रिया के लिए विनिर्माण संयंत्रों को भेजेगा ताकि बेहतर और गुणवतायुक्त उत्पाद सुनिश्चित किए जा सके। रेमंड, सम्पूर्ण देश में खादी उत्पादन करने वाले क्लस्टरों को भी डिजाइन इन्टरवेंशन (हस्तक्षेप) के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराएगा। यह पार्टनरशिप, खादी उत्पादन की संपूर्ण बहुमूल्य श्रृंखला में रेमंड द्वारा खादी के मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करने की दिशा में एक नयी कहानी बुनने का प्रतीक है।

रेमंड खादी उत्पाद, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बिक्री केन्द्रों के साथ-साथ सम्पूर्ण भारत के रेमंड दुकानों और प्रमुख ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर उपलब्ध होंगे।

आयोग द्वारा तिहाड़ जेल में मधुमक्खीपालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत

शहद मिशन के तहत 'स्वीट इकोनोमी' को बढ़ावा देने के लिए 50 युवा कैदियों को प्रशिक्षित किया गया

नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी की 'मधु क्रांति' और 'कौशल भारत' जैसी स्वप्निल परियोजनाओं से प्रेरित होकर, तिहाड़ जेल के युवा कैदियों के लिए पांच दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मंगलवार को जेल नंबर 5 में आयोजित किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रारंभ किए गए इस पाठ्यक्रम में 20 से 25 आयु वर्ग के 50 कैदियों ने भाग लिया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इस सम्बन्ध में प्रशिक्षणार्थियों को मधुमक्खी पालन के क्षेत्र और इसके महत्त्व के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी प्रदान की तथा मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने हेतु सुझाव दिए। उन्होंने, मधुमक्खी पालन के अर्थशास्त्र एंव शहद की मार्केटिंग सम्बंधित रणनीति तथा मधुमक्खी पालन के मूल्य के बारे में भी जानकारी दी। अध्यक्ष महोदय ने यह भी अवगत कराया कि "प्रशिक्षण के पश्चात् आयोग, जेल परिसर में हरियाली के मध्य 500 से अधिक मधुमक्खी बक्से स्थापित करेगा - ये बक्से न केवल प्रति वर्ष 12,500 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले शहद और 300 किलोग्राम बेहतर गुणवत्ता के मोम का उत्पादन करेंगे, बल्कि यह जेल परिसर में चारों ओर वनस्पतियों और जीवों को बढ़ावा देंगे, क्योंकि मधुमक्खियां करीब 2 किलोमीटर तक उड़ती हैं और परागण के माध्यम से फसल उत्पादन में 25 प्रतिशत की वृद्धि होती है। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा आयोग के तकनिकी विशेषज्ञ मधु मक्खी की प्रजातियों, उपनिवेश संगठन, श्रम विभाजन और मधु मक्खियों के जीवन चक्र, विभिन्न मौसमों के दौरान शहद मधुमक्खी कालोनियों के प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षण के दौरान और भी जानकारी प्रदान करेंगे।

श्री सक्सेना ने आगे कहा कि मधुमक्खी कालोनियों की जांच, मधुमक्खी दुश्मनों और रोगों, मधु निकासी और मोम शुद्धिकरण और वसंत, ग्रीष्म, मॉनसून, शरद ऋतु, सर्दियों के मौसम में मधुमक्खी कालोनियों का प्रबंधन और प्रबंधन के साथ मधुकोशों के सम्बन्धों की परीक्षा में व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। "हमारा उद्देश्य, प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए

"स्वीट क्रांति" के आह्वान के बाद, हमारे और प्रत्येक परिवार को उनके दैनिक उपयोग लिए शहद उपलब्ध कराना है। शहद, रोगप्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने और रक्त को शुद्ध करने में सहायक है | इसका औषधीय गुण है यह हृदय की बीमारियों और कैंसर जैसे प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं से शरीर की रक्षा करता है।" खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पूर्व में ही इस वर्ष दिल्ली में विभिन्न बागानों, फार्महाउसों और कॉलेजों में 5000 मधुमक्खी बक्से स्थापित करने की योजना बना ली है, दिल्ली में सामुदायिक रूप में शहद की खेती प्रारंभ करने से तदन्तर में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

महानिदेशक (जेल) श्री सुधीर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि कैदियों के पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी खेती में प्रशिक्षित होने के पश्चात् , कैदी कौशल सीख सकते हैं और जेल की अवधि समाप्त करने के पश्चात्, अपनी आजीविका कमाने के लिए इसको उपयोग में ला सकते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हाल के दिनों में 'हनी मिशन' का मशाल संवाहक बना है, वह मधुमक्खी बक्से के साथ छत्ते और अन्य विविध सामग्रियां प्रदान करेगा। उन्होंने आगे यह भी बताया कि आयोग, इसको उपयोग में लाने के बारे में भी प्रशिक्षित करेगा, हम जल्द ही अपने ही शहद का उत्पादन करेंगे और इसकी बिक्री भी करेंगे। यह कैदियों को सुधारने और उनका पुनर्वास करने का हिस्सा है।"

गुजरात के मुख्यमंत्री ने खादी संस्थाओं का दौरा किया

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी ने अपने अमरेली जिला के दौरे के दौरान 5 मई 2017 को सघन क्षेत्र योजना, वंडा जिला अमरेली का दौरा किया। संस्था के प्रमुख एवं गाँधीवादी श्री प्यारअली हालाणी ने माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया एवं संस्था की गतिविधियों से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

सघन क्षेत्र योजना वंडा संस्था गुजरात की एकमात्र संस्था है, जो मसलिन खादी उत्पादन कार्य करती है, जिसने पिछले वर्ष से बेंत व बांस मसलिन (Cane and Bamboo muslin) खादी का उत्पादन कार्य प्रारंभ किया है, इस प्रकार अन्य वनस्पति रेशों का मसलिन खादी में प्रयोग कर उत्कृष्ट प्रकार की खादी का उत्पादन करती है, पारंपरिक खादी कत्तिन बुनकरों के साथ साथ मुस्लिम कत्तिनें भी इस कार्य के साथ जुड़ी है। संस्था का अपना कोई बड़ा फुटकर बिक्री केन्द्र नहीं है, अधिकॉश बिक्री होलसेल अथवा खादी प्रदर्शनियों में बेची जाती है। संस्था सूती खादी में लगातार प्रयोग करती है। माननीय मुख्यमंत्री ने संस्था के कार्य से संतोष व्यक्त किया एवं कार्य की सराहना की।

समीक्षा बैठक

केन्द्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह, ने ग्रामोदय मुंबई में केवीआईसी की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव, एमएसएमई श्री अनिल कुमार तथा आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अन्शु सिन्हा की उपस्थिति में कार्यवाही संपन्न हुई।

श्री बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव एमएसएमई, आयोग मुख्यालय, मुंबई में केवीआईसी की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अन्शु सिन्हा भी उपस्थित थी।

सचिव, एमएसएमई द्वारा खादी बिक्री आउटलेट का दौरा

श्री के. के. जलान, आईएएस, सचिव, एमएसएमई, भारत सरकार, नई दिल्ली ने 1 9 मई 2017 को तंजौर के पश्चिम सर्वोदय संघ, तंजौर द्वारा संचालित वातानुकूलित बिक्री आउटलेट, खादी ग्रामोद्योग भवन का दौरा किया। आयोग द्वारा केआरडीपी योजना के अंतर्गत भवन के नवीनीकरण के लिए 210 लाख रूपए की निधि प्रदान की गई है।

अपने दौरे के दौरान सचिव महोदय ने भवन के परिसर में एक पौधे का भी रोपड़ किया। ☆

डीएलटीएफसी द्वारा पीएमईजीपी योजना के तहत 59 परियोजनाओं की सिफारिश की

पीएमईजीपी योजना के तहत दक्षिण अंडमान जिला से प्राप्त ऋण आवेदनों पर कारवाई करने हेतु जिला उद्योग केंद्र के लिए डीएलटीएफसी के साथ अंडमान और निकोबार खादी और ग्रामोद्योग मंडल के तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यबल समिति (डीएलटीएफसी) की 61 वीं बैठक 17 मई 2017 को जिला कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर में संपन्न हुई। यह बैठक श्री महेश कुमार गुप्ता, डीएएनआईसीएस, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण अंडमान जिला की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

इस बैठक के दौरान उद्योग निदेशक श्री अजीत आनंद, डीआईसी के महाप्रबंधक श्री गौतम मंडल, भारतीय स्टेट बैंक मुख्य कार्यालय के प्रमुख जिला प्रबंधक श्री पी.के. उम्मर फारूक, भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य प्रबंधक श्री मनोज कुमार, एमएसएमई-डीआई उप निदेशक [प्रभारी) श्री एमके अंजनाय, डीबीआरआईटी के विभागाध्यक्ष (इलेक्ट्रिकल) श्री अरुण श्रीवास्तव, अंडमान और निकोबार राज्य को-ऑपरेटिव बैंक, सिंडिकेट बैंक, एनवाईकेएस के प्रतिनिधि, लिटिल अंडमान पंचायत समिति के प्रधान सुश्री सीमा सरकार, हेवलॉक पंचायत समिति के सदस्य आलोक मृदा, शोल बे, ग्राम पंचायत प्रधान सुश्री मैरी पुष्पा ने भाग लिया। ☆

आयोग के अध्यक्ष को एल.आय.सी. ने खादी से जुडे कारीगरों के लाभार्थ रु.3,43,800/- का चैक सौंपा

दिनांक 15 मई 2017 को आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत एल आय सी द्वारा खादी से जुडे कारीगरों के कुल 573 बच्चों को प्रति विधार्थी 600/-रुपये का स्कोलरशिप राशि दावे के रूप में कुल रु.3,43,800/-का चैक आयोग को सौपा गया। आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय को यह चैक एलआयसी अधिकारियों द्वारा सौंपा गया। इस अवसर पर राज्य निदेशक श्री संजय हेडाऊ उपस्थित थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने एलआससी द्वारा खादी से जुडे कारीगरों के लिए किये गए कल्याणकारी प्रयासों सराहना की। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने एलआयसी अधिकारी को चरखा, स्मृतिचिन्ह के रुप में दिया।

इस अवसर पर राज्य कार्यालय में संस्था प्रतिनिधियों को एलआयसी आम आदमी योजना के संबंध में जानकारी भी दी गयी।

मधुमक्खीपालन को बढ़ावा देने हेतु बैठक

आयोग के निदेशक, एबीएफपीआई श्री एम. टी. वाकोडे ने बनास डेयरी पार्लर, जिला बनासकांठा के प्रतिनिधि के साथ हुई एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में आयोग के राज्य निदेशक, राज्य कार्यालय, अहमदाबाद श्री एस. जी. हेडाऊ और सहायक निदेशक श्री जगबीर सिंह भी उपस्थित थे।

आयोग के अध्यक्ष द्वारा नव निर्मित खादी भवन, वेजलपुर का उद्घाटन

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने दिनांक 14 मई, 2017 को श्री सर्वोदय विद्या विहार ट्रस्ट, जोरावरनगर संस्था के नव निर्मित खादी ग्रामोद्योग भवन, वेजलपुर, अमदाबाद का उदघाटन किया।

इस अवसर पर स्थानीय वेजलपुर विधानसभा के विद्यायक श्री किशोर भाई चौहाण, आयोग के राज्य निदेशक श्री संजय हेडाऊ, खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा वेजलपुर के स्थानीय लोग उपस्थित थे।

आयोग की भवन रिनोवेशन योजना के अंतर्गत संस्था को 15.00 लाख दिये गये हैं।

संस्था वर्ष 2009-10 में संस्था का उत्पादन 10.00 लाख रुपए था एवं 25 कारीगर कार्य करते थे, जो इस वर्ष बढकर 2016-17 में उत्पादन 81.00 लाख रूपए तथा कारीगरों की संख्या 118 हो गयी। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भवन में टेलरिंग सुविधा, ए/सी सुविधा, सीसीटीवी कैमेरे, डिजिटल भुगतान सुविधा, ग्राहकों के लिए मिनरल वॉटर सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

आयोग के अध्यक्ष महोदय ने संस्था के इस प्रयास की सराहना की।

अहमदाबाद में पी.एम.जी.पी. पर एस.एल.बी.सी. की बैठक संपन्न

गुजरात सरकार के प्रधान सचिव, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग श्री ए.के. राकेश की अध्यक्षता में 09 मई, 2017 को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक अहमदाबाद में संपन्न हुई।

इस अवसर पर वर्ष 2016-17 में उल्लेखनीय प्रगति के लिए बैंक ऑफ बडौदा को प्रथम, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दूसरे एवं कारपोरेशन बैंक को तीसरे स्थान के लिए बैठक के अध्यक्ष श्री ए.के. राकेश, आईएएस द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किये गए। बैठक में आयोग के राज्य निदेशक श्री संजय हेडाऊ ने सभी बैंकों को उनके बेहतर कार्य एवं प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद दिया।

अब अंग्रेज़ों को हुआ खादी से प्यार, हॉलीवुड में भी दिखी खादी की चमक

-चिरंतना भट्ट

इसी साल रिलीज़ हुई डिज़नी की इंग्लैंड में बनाई हुई फ़िल्म 'ब्यूटी एंड दी बीस्ट' में कई किरदारों ने खादी के कपड़े पहने है.

एक वक़्त था जब अंग्रेज़ो को खादी से परहेज़ था. उनके लिए वह एक ऐसा शस्त्र था जिसे हिंदुस्तानी लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए उठाया था.

लेकिन उस लड़ाई को अब कई साल बीत चुके हैं और वह खादी जिसे देख कर अंग्रेज़ मुंह फ़ेर लेते थे वह अब अंग्रेज़ी में बनने वाली फ़िल्मों तक पहुंच चुकी है. हॉलीवुड की फ़िल्मों में खादी यूज़ होने लगी है और इन फ़िल्मों से जुड़े डिज़ाईनर्स 'सस्टेनेबल फैब्रिक' के साथ काम करने पर बड़ा गर्व महसूस करते हैं.

वैसे हॉलीवुड अमेरिका में है और इस लिए हम सीधा ये तो नहीं कह सकते कि खादी अंग्रेज़ों तक पहुंची है. लेकिन इसी साल रिलीज़ हुई डिज़नी की इंग्लैंड में बनाई हुई फ़िल्म 'ब्यूटी एंड दी बीस्ट' में कई किरदारों ने खादी के कपड़े पहने है.

यही नहीं 2015 में बनी फ़िल्म 'पैन' के किरदार कैप्टन हुक ने पूरी फ़िल्म में खादी का शर्ट पहना है. जिस खादी को भारत में लोग राजनेताओं के साथ या तो एक्टिविज़म के साथ जोड़ते हैं, उसे फैशनेबल नहीं मानते उसी खादी का हॉलीवुड में बोलबाला है. गांधी की इस खादी को हॉलीवुड पहुंचाने का श्रेय गुजरात की शैलीनी शेठ अमीन को जाता है.

2015 में बनी फ़िल्म 'पैन' के किरदार कैप्टन हुक ने पूरी फ़िल्म में खादी का शर्ट पहना है.

मोरल फायबर के स्थापक और सीईओ शैलिनी वैसे तो आर्किटेक्चर पढ़ीं हैं लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से जुड़ी शैलीनी को खादी ने हमेशा आकर्षित किया. उन्होंने बताया, खादी सोशली और पर्यावरण के लिए भी सस्टेनेबल कपड़ा है. खादी बनाने में अन्य वस्त्र से कम बिजली लगती है और लोगों को रोज़गार भी मिलता है. वेब आधारित काम होने की वजह से हमारे पास विदेशी ग्राहकों की संख्या ज़्यादा है. वैसे अब भारत में भी खादी के

प्रति रुचि बढ़ रही है.

हॉलीवुड तक खादी पहुंचने की कहानी बताते हुए शैलीनी ने कहा, "लंदन के कुछ स्टोर्स में मोरल फाइबर से कपड़ा बिक्री के लिए जाता है. उसे देखकर एक महिला ने मुझसे संपर्क किया. क्लैर फ़िल्मों के लिए सोर्सिंग एजेंट का काम करती थी."

जब मैं लंदन गई तब क्लैर ने कहा कि मुझे जैक्लीन दुरां को मिलना है. मिलने से पहले मैंने उनके बारे में पढ़ा तो पता चला कि वह एक ब्रिटिश

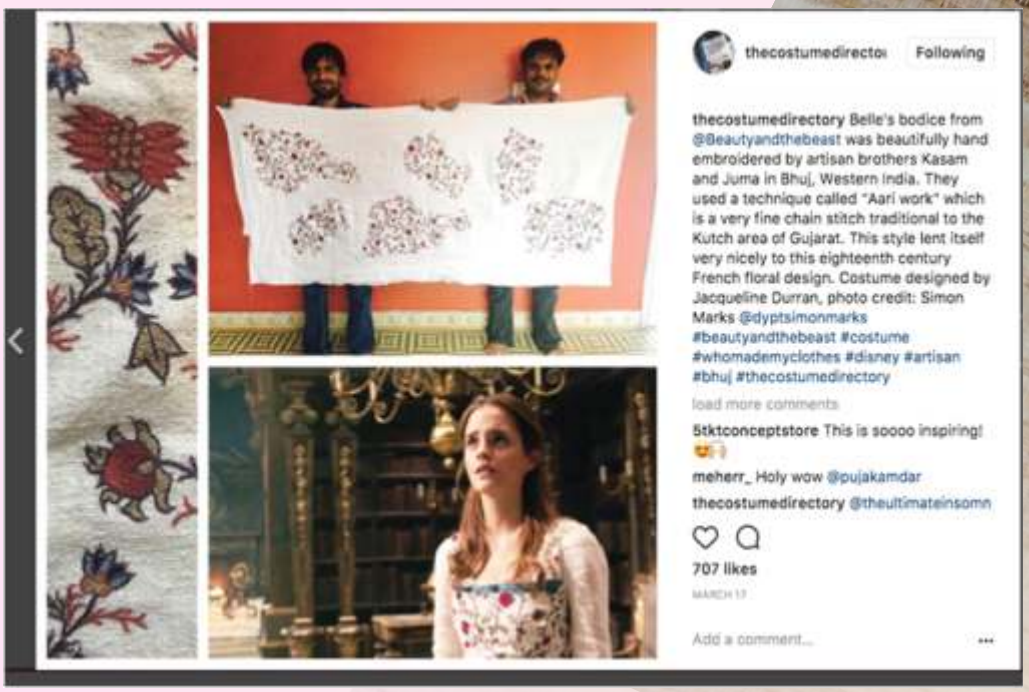

कॉस्ट्यूम डिज़ाईनर हैं जिन्हें 'प्राईड एंड प्रेजुडिस' के कॉस्ट्यूम के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया है. दुरां ने 'आन्ना केरेनिना', 'मैकबेथ' जैसी कई फ़िल्मों के लिए कपड़े डिज़ाइन किए हैं.

दुरां तब 'पैन' फ़िल्म पर काम कर रही थीं और उन्होंने कैप्टन हुक के किरदार के लिए खादी का शर्ट डिज़ाइन किया. कैप्टन हुक का किरदार उसी शर्ट में नज़र आता है. मोरल फाइबर से भेजे गए कपड़े फ़िल्म में इस्तेमाल किए गए और फ़िर डिज़्नी की फ़िल्म 'ब्यूटी एंड दी बीस्ट' में भी साथी कलाकारों के लिए खादी को चुना गया.

शैलीनी बताती हैं, "वहां इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी को लेकर सतर्क है और इसी लिए टेक्सटाइल उद्योग में सस्टेनेबिलिटी के विचार को ज़ोर दिया जा रहा है. अगली फ़िल्म 'मेरी मेग्डलीन' के लिए भी मोरल फाईबर के कपड़े लिए जाएंगे. 'ब्युटी एंड दी बीस्ट' फ़िल्म की मुख्य अभिनेत्री एम्मा वॉट्सन ने भी एथिकल और सस्टेनेबल फैशन के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया है."

भारत जिसे एक ज़माने में 'थर्ड वर्ल्ड कंट्री' कहा जाता था उसका ऐसा स्वदेशी फैब्रिक हॉलीवुड पहुंचा है जिससे अंग्रेज़ो का विरोध किया गया. स्वदेशी खादी को अपने डिज़ाईन में यूज़ करने वाली जैक्लीन दुरां भी ब्रिटिश महिला है.

भारत की अन्य कलाएं भी हॉलीवुड पहुंच रही हैं. जैसे 'ब्यूटी एंड दी बीस्ट' फ़िल्म में ऐम्मा वॉट्सन के पहने हुए एक ड्रेस पर भुज, गुजरात के जुमा और कासम ने आरी वर्क से कढ़ाई कर के बेल बूटे का काम किया था.

साभार:न्यूज़ 18 इंडिया

आयोग की 644वीं बैठक का कार्यवृत्त

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 644वीं बैठक दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थिति थे:- श्री विनय कुमार सक्सेना, अध्यक्ष, श्री जय प्रकाश तोमरआंचलिक सदस्य (मध्य अंचल),श्री जी. चन्द्रमौलि आंचलिक सदस्य (दक्षिण अंचल),डॉ. संगीता कुमारीआंचलिक सदस्य (पूर्वी अंचल),श्री नारायण चंद्र बोरकाटकीआंचलिक सदस्य (पूर्वोत्तर अंचल),श्री अशोक भगतविशेषज्ञ सदस्य (अनुसंधान और विकास),श्री राजेंद्र प्रताप गुप्ताविशेषज्ञ सदस्य (विपणन),श्रीमती सुमन लता गुप्ताउप महाप्रबंधक, एसएमई, भारतीय स्टेट बैंक,श्री बी. एच. अनिल कुमार संयुक्त सचिव (सु.ल.म.उ.), श्रीमती अंशु सिन्हा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, श्रीमती ऊषा सुरेश,वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। बैठक में अन्य अधिकारी में श्री मोहित जैन मुख्य सतर्कता अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, श्री सत्य पाल,संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, श्री के.एस.राव, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रमंरोसूका / प्रचार / विपणन / आईटी /एफबीएए / विधिक मामले), श्री वाई. के. बारामतीकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प. अं. / क्ष. नि. / सं. से. / वि. प्रौ. / एसबीसी / एलआर/प्रशासन), श्री डी. धनपाल, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (खादी / केपीएम / आरआईडी / अर्थ-अनुसंधान), श्री सत्य नारायण, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयोग प्रकोष्ठ) उपस्थित थे।

शुरुआत में उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयोग प्रकोष्ठ) ने सभी सदस्यों का खादी और ग्रामोद्योग आयोग की नई दिल्ली में दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को आयोजित 644वीं बैठक में स्वागत किया।

मद संख्या 01: खादी और ग्रामोद्योग आयोग की दिनांक 29 मार्च, 2017 को मुंबई में आयोजित 643वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

आयोग ने दिनांक 29 मार्च, 2017 को मुंबई में आयोजित खादी और ग्रामोद्योग आयोग की 643वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की। कार्यवृत्त की पुष्टि के दौरान उठाए गए मुद्दों को अनुलग्नक-I में अवलोकनार्थ रखा गया है।

मद संख्या 02: दिनांक 29 मार्च, 2017 को अहमदाबाद में आयोजित खादी और अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट।

आयोग ने दिनांक 29 मार्च, 2017 को अहमदाबाद में आयोजित आयोग की 642वीं बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर अनुलग्नक-II में रखे 'अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट' से उठे मुद्दों को नोट किया।

मद संख्या 03: खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थानांतरण नीति पर प्रशासन निदेशालय का प्रस्ताव।

1. आयोग ने प्रशासन निदेशालय के प्रस्ताव पर विस्तार पूर्वक चर्चा की और निम्नलिखित अवलोकन किए:

1. कॉलम संख्या 6 में बार-बार उल्लिखित 'केन्द्रीय कार्यालय कर्मचारी' के रूप में विवरण तथा मसौदा दिशानिर्देशों में अन्यत्र इस प्रकार के उद्धरणों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि 'केन्द्रीय कार्यालय कर्मचारी' के नाम पर कोई अलग संवर्ग नहीं है।

2. मसौदा प्रस्ताव की पेचीदगियों को ध्यान में रखते हुए; आयोग ने "सामान्य" (मद संख्या 21) के अंतर्गत शर्त संख्या 7 एवं 8 (कॉलम संख्या 5) को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया:

7. आयोग को किसी भी कर्मचारी को आयोग के हित में किसी भी समय, कहीं भी तथा कार्य आवश्यकतानुसार किसी भी अवधि के लिए स्थानांतरित करने की शक्तियां प्राप्त हैं, और ऐसे मामलों में स्थानांतरण आदेश को कार्यान्वित करने के दौरान आयोग की स्थानांतरण नीति कोई भी

बाधा नहीं बनेगी।

8. किसी भी अत्यावश्यकता / आकस्मिकता / राष्ट्रीय विपदा इत्यादि के दौरान, आयोग के पास किसी भी कर्मचारी को आयोग के हित में किसी भी समय, कहीं भी तथा कार्य आवश्यकतानुसार किसी भी अवधि के लिए स्थानांतरित करने का अधिकार होगा; और ऐसे मामलों में स्थानांतरण आदेश को कार्यान्वित करने के दौरान आयोग की स्थानांतरण नीति कोई भी बाधा नहीं बनेगी।

3.आयोग ने आगे निर्णय लिया कि चूंकि 'राज्य संवर्ग' को 'अखिल भारत संवर्ग' के तौर पर मौजूदा/विद्यमान भती नियमों में प्रतिस्थापित किया गया है, आयोग के कर्मचारियों को राज्य/मंडलीय कार्यालयों से किसी भी अन्य राज्य/मंडलीय कार्यालयों (अंतर प्रदेशीय स्थानांतरण) में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसमें केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई से किसी भी राज्य/मंडलीय कार्यालय तथा किसी भी राज्य/मंडलीय कार्यालय में किया जाना शामिल है, और इसे मसौदा स्थानांतरण दिशानिर्देशों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

4. आयोग ने आगे निर्देशित किया कि मौजूदा/विद्यमान भती नियमों के अनुसार अनुमोदित कर्मचारियों के पदनामों का उपयोग 'मसौदा स्थानांतरण नीति/दिशानिर्देशों'' में किया जाना चाहिए।

5. आयोग ने संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. के अवलोकनों पर सहमति जताई और निर्देश दिया कि स्थानांतरण के विचारार्थ/औचित्यपरक क्षेत्र होने के लिए मसौदा प्रस्ताव में शब्द "समकक्षों" के उपयोग को बंद किया जाना चाहिए जैसा कि मसौदा स्थानांतरण नीति/दिशानिर्देशों" के क्रम संख्या 3 कॉलम संख्या 4 एवं 6 में देखा गया है।

6.आयोग ने संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. के इस अवलोकन पर भी सहमति जताई और निर्देशित किया कि लेखा-परीक्षकों, जो अखिल भारत संवर्ग से संबंध रखते हैं, को राज्य/मंडलीय कार्यालयों से किसी भी अन्य राज्य/मंडलीय कार्यालयों (अंतर प्रदेशीय स्थानांतरण) में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसमें केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई से किसी भी राज्य/मंडलीय कार्यालय तथा राज्य/मंडलीय कार्यालय से केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में किया जाना शामिल है, और इसे मसौदा स्थानांतरण दिशानिर्देशों में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

7.अंत में, आयोग ने निर्देशित किया कि सभी उपरोक्त संशोधनों को सम्मिलित किया जाए, और पूरे 'मसौदा स्थानांतरण नीति/दिशानिर्देशों' को पुनः तैयार किया जाना चाहिए, जो कि बहुत ही विशिष्ट हो तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार हो, तथा इसे आयोग की आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जाए।

कार्रवाई: उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)

मद संख्या 04: खादी प्रमाणपत्र निदेशालय द्वारा खादी प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण के संबंध में प्रस्ताव।

1. आयोग ने प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया और अवलोकन किया कि नई खादी संस्थाओं के ऐसे सौ से अधिक मामले हैं जिन्हें हाल ही में आयोग की सीधी सूची में शामिल किया गया है, लेकिन उनका 'खादी पंजीकरण प्रमाणपत्र' उनके द्वारा निबंधनों व शर्तों की पूर्ति न कर पाने के कारण लंबित है, जिस कारण उक्त संस्थाएं अपनी खादी उत्पादन गतिविधियों को प्रारंभ नहीं कर पा रही हैं।

2. इसलिए आयोग ने आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत किया कि 'समयबद्ध अस्थायी प्रमाणपत्र' ऐसी सभी संस्थाओं को जारी कर सकें, जिसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया जाए कि उनके प्रमाणपत्र की वैधता कमियों/दस्तावेजों/स्पष्टीकरणों के अभाव के मामले में समाप्त हो जाएंगी यदि इनकी पूर्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात तीन माह की निर्धारित समयवाधि के भीतर नहीं की जाती है।

3. आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त सुविधा सभी ''खादी प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन

आवेदकों'' को प्रदान किया जाए, जिससे कि "ऑफलाइन खादी पंजीयन प्रणाली " को समाप्त किया जा सके।

4. खादी पंजीयन प्रमाणपत्रों के मामले में निम्नलिखित निर्णय आयोग द्वारा पूर्व में लिए गए थे जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

ए) आयोग की मुंबई में आयोजित 631वीं बैठक दिनांक 29.03.2016- खादी प्रमाणपत्रों को खादी मार्क विनियम, 2013 के साथ जोड़ने पर समिति द्वारा लिए गए निर्णय के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया (मद संख्या 5 के अंतर्गत बिन्दु संख्या 1)।

बी) आयोग की भुवनेश्वर में आयोजित 636वीं बैठक दिनांक 29.08.2016- प्रक्रिया में होने वाले विलंब को दूर करने तथा इसे गति देने के लिए आयोग ने आगे सभी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्राधिकृत किया कि संस्थाओं के खादी पंजीयन प्रमाणपत्रों को अंचलवार नवीनीकृत करें (मद संख्या 7 के अंतर्गत बिन्दु संख्या 14)।

सी) आयोग की अहमदाबाद में आयोजित 642वीं बैठक दिनांक 27.02.2017- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुराने खादी प्रमाणपत्रों को आचंलिक समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर/जारी किया जाएगा (मद संख्या 7 के अंतर्गत बिन्दु संख्या 1 - अनुलग्नक-1)।

आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 01.04.2017 से संस्थाओं को प्रमाणपत्र खादी मार्क विनियम के अनुसार जारी किए जाएंगे (मद संख्या 7 के अंतर्गत बिन्दु संख्या 2 - अनुलग्नक-1)।

5. 'खादी पंजीयन प्रमाणपत्रों' को जारी करने के संबंध में उपरोक्तानुसार विभिन्न निर्णयों के क्रम में आयोग ने निर्णय लिया कि खादी प्रमाणपत्र विनियम तथा खादी मार्क विनियम को एक साथ विलय करते हुए एक साझा विनियम तैयार किया जाए, और एक आंतरिक समिति का गठन संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाए, जिससे कि विनियमों को एक साथ विलय करके एक माह के भीतर एक साझा कार्यनीति को तैयार किया जा सके तथा इसे आयोग की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

6. आयोग ने इस बार पर भी जोर दिया कि संबंधित अंचलों के आंचलिक सदस्य आंचलिक खादी प्रमाणपत्र समिति का नेतृत्व करेंगे और आंचलिक समिति एक आंचलिक प्रमाणपत्र समिति के बतौर कार्य करेगी और आंचलिक प्रमाणपत्र समिति की जिम्मदारियों का वहन करेगी।

7. जैसा कि संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. द्वारा अवगत कराया गया, आयोग ने निर्णय लिया कि खादी प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण हेतु पूर्व में प्राप्त सभी आवेदनों पर वर्तमान प्रणाली के अधीन विचार किया जाएगा।

8. उपरोक्त वर्णित अनुसार विभिन्न निर्णयों/सुझावों के क्रम में; तथा खादी गतिविधियों को निरंतर रूप से चलते रहने हेतु सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने निर्णय लिया कि मौजूदा केन्द्रीय प्रमाणपत्र समिति तथा केन्द्रीय खादी मार्क समिति को तब तक जारी रखा जाए जब तक कि एक समेकित/साझा दिशानिर्देश खादी मार्क प्रमाणपत्र के कार्यान्वयन के लिए तैयार नहीं कर लिए जाते, और आयोग ने प्रमाणपत्र के मामले पर अंतिम निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्राधिकृत किया और आयोग को तदानुसार अवगत कराया जाए।

कार्रवाई: उप निदेशक (खादी प्रमाणपत्र)

मद संख्या 05: 'आयोग द्वारा आंतरिक स्रोत सृजन तथा विभिन्न उद्देश्यों हेतु इसका उपयोग' के संबंध में लेखा निदेशालय का प्रस्ताव।

1. आयोग ने आंतरिक स्रोत सृजन तथा विभिन्न उद्देश्यों हेतु इसके उपयोग के संबंध में लेखा निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और इसे अनुमोदित किया। इस बात पर जोर दिया गया कि मंत्रालय के निर्देश के क्रम में आंतरिक स्रोत सृजन के प्रयास प्रत्येक निदेशालयों द्वारा किए जाने चाहिए।

2. आगे, आयोग ने संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. के अवलोकनों को नोट किया कि आयोग को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रति आवेदन कोई भी शुल्क नहीं लेना चाहिए (जैसा कि रु.200/- प्रस्तावित है)। वित्तीय सलाहकार ने इस बात पर जोर दिया कि 7वें वेतन की देयताओं की पूर्ति के वहन के लिए आंतरिक स्रोत सृजन हेतु मंत्रालय के निर्देशों तथा उपयोगकर्ता प्रभार के लिए वित्त मंत्रालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आवेदकों पर शुल्क प्रभारित करना उचित होगा।

3. आयोग ने अध्यक्ष महोदय के अवलोकनों को भी नोट किया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आवेदकों से ऑनलाइन पंजीयन प्रभार शुल्क लेने से न केवल खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए बहुप्रतीक्षित आंतरिक स्रोत सृजन का निर्माण होगा, अपितु इससे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के प्रति गंभीर आवेदक भी इससे सामने आने के लिए प्रोत्साहित होंगे । इसलिए आयोग ने निर्णय लिया कि सामान्य वर्ग के आवेदकों से 200.00 रुपए तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों से 100 रुपए प्रति आवेदन ऑनलाइन पंजीयन शुल्क लिया जाएगा।

4. आगे, आयोग ने संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. के अवलोकनों को नोट किया कि चूंकि ज्यादातर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के अनुरूप बनाया जा रहा है, पाठ्यक्रम पर आधारित उच्चतम पंजीयन शुल्क क्षमता निर्माण निदेशालय, केवीआईसी द्वारा आयोजित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थियों से प्रभारित किया जा सकता है।

5. इसलिए आयोग ने निर्णय लिया कि एक समग्र प्रस्ताव उपरोक्त क्रम में तैयार किया जाए और इसे सरकार के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

कार्रवाई: सभी कार्यक्रम/उद्योग निदेशालय

मद संख्या 06: 'वर्ष 2017-18 से विभागीय तथा गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण के कार्यान्वयन हेतु संशोधित दिशानिर्देशों' के संबंध में क्षमता निर्माण निदेशालय का प्रस्ताव।

1. आयोग ने 'वर्ष 2017-18 से विभागीय तथा गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण के कार्यान्वयन हेतु संशोधित दिशानिर्देशों' के संबंध में क्षमता निर्माण निदेशालय के प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और इसे तीन मोड्यूल के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया; (1) छात्रवृत्ति आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम (2) मास्टर ट्रेनरों/स्थानीय कौशल प्रशिक्षकों को शामिल करके आयोजित किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण (स्व वित्त पोषित प्रशिक्षण कार्यक्रम) (3) 'पेशेवर प्रशिक्षण सहयोगियों' (पीटीए) को शामिल करके कौशल प्रशिक्षणआयोजित करना।

2. आयोग ने संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. के सुझावों पर सहमति जताई कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विभागीय के साथ-साथ गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों में भी आयोजित किया जा रहा है जो कि एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा) के अनुरूप होने चाहिए।

3. आयोग ने संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. के अवलोकनों पर सहमति जताई कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि एनएसक्यूएफ के साथ केवीआईसी के विभागीय तथा गैर-विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों को एनएसक्यूएफ की 'साझेदार संस्थाओं' के रूप में मान्यता/सहबद्धता प्रदान करने हेतु एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाए ताकि एनएसक्यूएफ अपने कौशल सक्षम प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को केवीआई के प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से संचालित कर सके, और इस प्रयास से केवीआईसी को अतिरिक्त राजस्व के सृजन में भी मदद मिल सकेगी।

4. आयोग ने संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. के

अवलोकनों पर भी सहमति जताई कि मधुमक्खीपालन जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास स्वयं की अनूठी विशेषज्ञता है, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की अपनी 'सेक्टर कौशल परिषद' होनी चाहिए।

कार्रवाई: निदेशक (क्षमता निर्माण)

निदेशक (वन आधारित उद्योग)

मद संख्या 07: दिनांक 27.02.2017 को अहमदाबाद में आयोजित स्थायी वित्त समिति (2016-17) की 11वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

आयोग ने दिनांक 27.02.2017 को अहमदाबाद में आयोजित स्थायी वित्त समिति (2016-17) की 11वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

सचिव (स्थायी वित्त समिति)

मद संख्या 08: 'हवाई अड्डों पर बिक्री केन्द्र खोलने के लिए निर्दिष्ट दिशानिर्देशों में संशोधन' के संबंध में विपणन निदेशालय का प्रस्ताव।

आयोग ने 'हवाई अड्डों पर बिक्री केन्द्र खोलने के लिए निर्दिष्ट दिशानिर्देशों में संशोधन' के संबंध में विपणन निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया:

1. आयोग ने इस अनिवार्य दिशानिर्देश में छूट दी कि हवाई अड्डों के कार्यक्षेत्र के नजदीक कम से के 5 से 6 अच्छी संस्थाएं बिक्री केन्द्र के संचालन के लिए होनी चाहिए और अनुमोदित किया कि बिक्री केन्द्र को किसी एक संस्था/फेडेरेशन द्वारा भी संचालित किया जा सकता है बशर्ते कि वह एक संस्था/फेडेरेशन विभिन्न संस्थाओं के उत्पादों को बेचने पर सहमत हो।

2. आयोग ने यह अनुमोदित किया कि बिक्री केन्द्रों की बिक्री से हुई आमदनी को संस्थाओं/फेडेरेशनों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा तथा बिक्री से हुई आमदनी का 5% प्रशासनिक प्रभार के तौर पर विपणन निदेशालय के केन्द्रीयकृत बैंक खाते में प्रत्येक माह की 5 तारीख को जमा किया जाएगा।

3. आयोग ने निर्देश दिया कि पूरे देश भर में अन्य हवाई अड्डों पर भी इसी प्रकार के बिक्री केन्द्रों को खोलने के प्रयास किए जाने चाहिए।

कार्रवाई: निदेशक (विपणन)

मद संख्या 09: आईडीसीओ, ओडिशा के साथ बकाया का निबटान करने तथा आईडीसीओ द्वारा केवीआईसी, भुवनेश्वर को पट्टे पर दी गई भूमि का उपयोग करने के संबंध में खादी कच्चा माल निदेशालय का प्रस्ताव।

आयोग ने आईडीसीओ, ओडिशा के साथ बकाया का निबटान करने तथा आईडीसीओ द्वारा केवीआईसी, भुवनेश्वर को पट्टे पर दी गई भूमि का उपयोग करने के संबंध में खादी कच्चा माल निदेशालय के प्रस्ताव पर विचार किया और निम्नानुसार अनुमोदन किया:

1. आयोग ने बकायों के निबटान के सापेक्ष रु.8,60,407.36 का भुगतान आईडीसीओ, ओडिशा को करने के लिए अनुमोदिन प्रदान किया, जो कि भूमि किराया का ब्याज तथा दंडात्मक ब्याज के लिए है और यह सीएसपी के केन्द्रीयकृत बैंक खाते में संचित ब्याज से वहन किया जाएगा।

2.आगे, आयोग ने संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. मंत्रालय के सुझाव की जांच करने का निर्णय लिया जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र की औद्योगिक संभावना पर विचार करते हुए इस स्थान पर एक इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना का सुझाव दिया था।

कार्रवाई: निदेशक (खादी कच्चा माल)

मद संख्या 10: आगे की जाने वाली कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए विनोबा सेवा समिति, जयपुर के मुद्दों पर खादी निदेशालय का प्रस्ताव।

आयोग ने विनोबा सेवा समिति, जयपुर के मुद्दों से संबंधित खादी निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और निम्नानुसार निर्णय लिया:

यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मामले को आयोग की 645वीं बैठक में चर्चा के लिए रखा जाए।

कार्रवाई: निदेशक (खादी)

मद संख्या 11: आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/उद्योगों के अंतर्गत उपलब्धियों के संबंध में अर्थ अनुसंधान निदेशालय का प्रस्ताव।

1.आयोग ने अर्थ अनुसंधान निदेशालय द्वारा आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों/उद्योगों के शीर्ष के अंतर्गत वर्णित उपलब्धियों को नोट किया।

2.आयोग ने अस्थायी प्रकृति के आकंडों तथा वास्तविक आंकड़ों को भी नोट किया जो मई 2017 के अंत तक अपेक्षित हैं।

3 .आयोग ने सदस्य (दक्षिण अंचल) के अवलोकनों को नोट किया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आंकड़ों को ग्रामोद्योग के कुल आंकड़ों से अलग किया जाना चाहिए और इसे पृथक तौर पर दर्शाया जाना चाहिए जिससे कि खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र में ग्रामोद्योगों के वास्तविक कार्यनिष्पादन का आकलन किया जा सके।

4.आगे, आयोग ने निर्णय लिया कि मौजूदा ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थिति का जायजा लेने के लिए पूरे खादी ग्रामोद्योगी क्षेत्र का एक विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे कि उत्पादन, बिक्री, रोजगार, अधोसंरचना, प्रयुक्त तकनीक इत्यादि की स्थिति का पता लगाया जा सके और इस हेतु एक पूर्ण डाटाबेस तैयार किया जा सके।

कार्रवाई: निदेशक (अर्थ अनुसंधान)

मद संख्या 12: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय।

मद संख्या 12.1: खादी संस्थाओं को जारी किए गए बेबाकी प्रमाणपत्रों के संबंध में खादी निदेशालय का समीक्षा नोट।

1. आयोग ने केवीआईसी ऋण के निबटान हेतु बेबाकी प्रमाणपत्र जारी किए जाने के मामले पर विचार किया जहां इस बारे में राज्य/मंडलीय कार्यालयों द्वारा और साथ ही केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई में संबंधित निदेशालय द्वारा बेबाकी प्रमाणपत्र जारी किए जाने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, यद्यपि संस्थाओं द्वारा केवीआईसी के ऋण का निबटान किया जा चुका है।

2. आयोग ने अपनी 643वीं बैठक में निर्णय लिया था कि आयोग की वर्तमान 644वीं बैठक में निम्न विवरण प्रस्तुत किया जाए; (1) बेबाकी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या (2) जारी किए गए बेबाकी प्रमाणपत्रों की संख्या (3) राज्य/मंडलीय कार्यालयों में लंबित बेबाकी प्रमाणपत्रों की संख्या, परन्तु 644वीं बैठक (मौजूदा बैठक) में केवल खादी से जुड़े मुद्दों को कार्यसूची मद संख्या 12.1 में रखा गया है, जबकि संस्थाओं की स्थिति, जिन्होंने ग्रामोद्योग के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया था, को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.आयोग ने संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. मंत्रालय के अवलोकनों को भी नोट किया कि एक ओर जहां संस्थाओं के मांग खातों का रखरखाव राज्य निदेशकों द्वारा किया जा रहा है, वसूली केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर की जा रही है, परिणामस्वरूप मिलान में विसंगति हो रही है और बेबाकी प्रमाणपत्रों को जारी करने में विलंब हो रहा है।

4.आयोग ने संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. मंत्रालय के अवलोकनों को भी नोट किया और निर्णय लिया कि बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु संस्थाओं के उद्देशय की विस्तार पूर्वक जांच किए जाने की जरूरत है जिससे कि बेबाकी प्रमाणपत्रों पर जोर देने वाली संस्था को अलग किया जा सके जिनका उद्देश्य केवल संस्था की संपत्ति को बेचना मात्र है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि बेबाकी प्रमाणपत्र किसी भी संस्था को अपनी संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं देता है।

5. इस संबंध में आयोग ने अध्यक्ष के सुझावों पर सहमति जताई और निर्णय लिया कि प्रत्येक बेबाकी प्रमाणपत्र को समयबद्ध होना चाहिए और प्रत्येक बेबाकी प्रमाणपत्र में एक फुटनोट अंकित किया जाना चाहिए कि यह बेबाकी प्रमाणपत्र संस्था को केवल लेखा उद्देश्यों के लिए जारी किया गया है और यह बेबाकी प्रमाणपत्र संस्था की किसी भी चल अथवा अचल संपत्ति के निबटान के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है।

6. आयोग ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गयी ऑनलाइन एमडीए संवितरण प्रणाली के बारे में वित्तीय सलाहकार के अवलोकनों को नोट किया, जिसमें 'व्यू विंडो' सुविधा को सभी राज्य निदेशकों के साथ-साथ संस्थाओं के लिए सक्षम बनाया गया है कि प्रारंभ की गई वसूली इत्यादि के संबंध में विवरणों का सत्यापन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से कर सकें।

7.आयोग ने अध्यक्ष महोदय के सुझावों पर भी सहमति जताई और निर्णय लिया कि सभी खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं का एक डाटाबेस तैयार किया जाए, जिन्होंने (1) ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया है, कार्यक्रम को प्रभावी तौर पर कार्यान्वित किया और अब वे ऋण को ब्याज सहित वापस करने की इच्छुक हैं (2) आंशिक तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई संस्थाएं जो इकाइयां स्थापित नहीं कर सकीं अथवा प्रारंभ की गई वूसली के सापेक्ष कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं कर सकीं और अब केवीआईसी को प्रारंभिक राशि वापस करने की इच्छुक हैं। इस डाटा को संस्थाओं/व्यक्तियों/राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड-वार एकत्र किया जाएगा और लंबित वसूलियों की एक सूची तैयार की जाएगी।

8.आगे, आयोग ने निर्णय लिया कि खादी और ग्रामोद्योगी डाटा को आयोग के सभी सदस्यों और सभी संबंधितों को 15 कार्य दिवसों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा और मामले पर विस्तृत दिशानिर्देशों को आयोग के आगामी बैठक में रखा जाएगा।

9.इस परिप्रेक्ष्य में आयोग को अवगत कराया गया कि खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं के बकाया ऋण को माफ करने हेतु एक प्रस्ताव मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के समक्ष भी लंबित है।

10. आगे, आयोग ने निर्णय लिया कि भूमि और संपत्ति के निबटान का मामला उन संस्थाओं से संबंधित नहीं है जिन्होंने ग्रामाद्योग ऋण प्राप्त किया है, इसलिए ऐसी ग्रामोद्योगी संस्थाओं को सम्यक बंधक विलेखों, व्यक्तिगत गारंटी दस्तावेजों, बेबाकी प्रमाणपत्रों इत्यादि को वापस देने में कोई हिचकिचाहट नहीं की जानी चाहिए, जिन्होंने केवीआईसी को पूरी ऋण राशि वापस लौटा दी है।

11. आयोग ने संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. के सुझावों पर विचार किया और फील्ड स्तर के कार्यालय के लिए ऋण की वसूली करने तथा ऐसे आंशिक कार्यप्रदर्शन वाली अथवा गैर-कार्यनिष्पादन वाली सस्थाओं हेतु एक वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय लिया। कार्रवाईः

निदेशक (खादी) निदेशक (ग्रामोद्योग समन्वय)

निदेशक (लेखा)

मद संख्या 12.2: सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत 334 पदों को मैसर्स एडसिल इंडिया लिमिटेड, नोएडा के माध्यम से भरने के संबंध में प्रशासन एवं मानव संसाधन निदेशालय की टिप्पणी।

आयोग ने वित्तीय सलाहकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मैसर्स एडसिल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 10.04.2017 को हुई चर्चा परिणामों को नोट किया, जैसा कि इसे आयोग के समक्ष प्रस्ताव/नोट में उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और आयोग ने उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग में सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत 334 पदों को भरने संबंधी कार्य मैसर्स एडसिल इंडिया लिमिटेड, नोएडा को सौपने के लिए आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा। कार्रवाईः उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)

मद संख्या 12.3: दिनांक 17-18 अप्रैल, 2017 को रांची, झारखंड में आयोजित अभ्यारण्य कार्यशाला के संबंध में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम निदेशालय की समीक्षा नोट।

आयोग ने दिनांक 17-18 अप्रैल, 2017 को रांची, झारखंड में आयोजित अभ्यारण्य कार्यशाला की स्थिति, की गई कार्रवाई तथा अनुशंसाओं को नोट किया। कार्रवाईः निदेशक (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम)

मद संख्या 12.4: माइक्रो हनी-बी मिशन (2017-2018)

के लिए कार्य-योजना के संबंध में वन आधारित उद्योग निदेशालय का प्रस्ताव।

आयोग ने माइक्रो हनी-बी मिशन (2017-2018) के लिएकार्य-योजना के संबंध में वन आधारित उद्योग निदेशालय के प्रस्ताव पर चर्चा की और सैद्धांतिक रूप से निम्नलिखित लक्ष्यों को अनुमोदन प्रदान किया:

कार्रवाई: निदेशक (वन आधारित उद्योग)

1	भौतिक लक्ष्य	20,566 व्यक्ति
2	वित्तीय लक्ष्य	रु.6.00 करोड़
3	आंतरिक स्रोत सृजन	रु.59.25 लाख

आगामी बैठक:

उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आयोग प्रकोष्ठ) द्वारा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के साथ समाप्त बैठक हुई एवं आयोग तथा स्थायी वित्त समिति की अगली बैठक क्रमश: 30 और ३१ मई, २०१७ को प्रातः १०.०० बजे शिमला में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

*****

अनुलग्नक-I

29 मार्च, 2017 को मुंबई में आयोजित आयोग की 643वीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि पर चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दे।

१.मद संख्या 5 (अनुलग्नक-I) संस्थाओं द्वारा भुगतान किए गए केवीआईसी ऋण के निपटान के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने के संबंध में:

१.आयोग ने राज्य / मंडलीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय केवीआईसी, मुंबई के संबंधित निदेशालयों की ओर से भी ऐसी संस्थाओं, जिन्होंने केवीआईसी ऋण का निबटान कर दिया है, उन्हें एनओसी जारी करने में अनावश्यक देरी पर सदस्य (मध्य क्षेत्र) के अवलोकन को नोट किया, यद्यपि संस्थाओं ने केवीआईसी के ऋण का भुगतान कर दिया है।

२.सदस्य (मध्य क्षेत्र) ने अवलोकन किया कि आयोग की ६४३वीं बैठक में आयोग ने निम्नलिखित विवरण ६४४वीं बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था (१) एनओसी जारी करने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या (२) जारी की गई एनओसी की संख्या और (३) राज्य / मंडलीय कार्यालयों में लंबित एनओसी की संख्या। परंतु वर्तमान बैठक (६४४वीं) में कार्यसूची मद संख्या १२.१ के अंतर्गत केवल खादी से संबन्धित मामले को ही प्रस्तुत किया गया है, जबकि जिन संथाओं ने ग्रामोद्योगी ऋण लिया है उनके बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.आयोग ने संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. मंत्रालय के अवलोकनों को भी नोट किया कि एक ओर जहां संस्थाओं के मांग खातों का रखरखाव राज्य निदेशकों द्वारा किया जा रहा है, वसूली केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर की जा रही है, परिणामस्वरूप मिलान में विसंगति हो रही है और बेबाकी प्रमाणपत्रों को जारी करने में विलंब हो रहा है।

4.आयोग ने संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. मंत्रालय के अवलोकनों को भी नोट किया और निर्णय लिया कि बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु संस्थाओं के उद्देशय की विस्तार पूर्वक जांच किए जाने की जरूरत है जिससे कि बेबाकी प्रमाणपत्रों पर जोर देने वाली संस्था को अलग किया जा सके जिनका उद्देश्य केवल संस्था की संपत्ति को बेचना मात्र है।

5.इस संबंध में आयोग ने अध्यक्ष के सुझावों पर सहमति जताई और निर्णय लिया कि प्रत्येक बेबाकी प्रमाणपत्र को समयबद्ध होना चाहिए और प्रत्येक बेबाकी प्रमाणपत्र में एक फुटनोट अंकित किया जाना चाहिए कि यह बेबाकी प्रमाणपत्र संस्था को केवल लेखा उद्देश्यों के लिए जारी किया गया है और यह बेबाकी प्रमाणपत्र संस्था की किसी भी चल अथवा अचल संपत्ति के निबटान के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है।

6.आयोग ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गयी ऑनलाइन एमडीए संवितरण प्रणाली के बारे में वित्तीय सलाहकार के अवलोकनों को नोट किया, जिसमें

'व्यू विंडो' सुविधा को सभी राज्य निदेशकों के साथ-साथ संस्थाओं के लिए सक्षम बनाया गया है कि प्रारंभ की गई वसूली इत्यादि के संबंध में विवरणों का सत्यापन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से कर सकें।

7.आयोग ने अध्यक्ष महोदय के सुझावों पर भी सहमति जताई और निर्णय लिया कि सभी खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं का एक डाटाबेस तैयार किया जाए, जिन्होंने (1) ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया है, कार्यक्रम को प्रभावी तौर पर कार्यान्वित किया और अब वे ऋण को ब्याज सहित वापस करने की इच्छुक हैं (2) आंशिक तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई संस्थाएं जो इकाइयां स्थापित नहीं कर सकीं अथवा प्रारंभ की गई वूसली के सापेक्ष कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं कर सकीं और अब केवीआईसी को प्रारंभिक राशि वापस करने की इच्छुक हैं। इस डाटा को संस्थाओं/व्यक्तियों/राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड-वार एकत्र किया जाएगा और लंबित वसूलियों की एक सूची तैयार की जाएगी।

8 . आगे, आयोग ने निर्णय लिया कि खादी और ग्रामोद्योगी डाटा को आयोग के सभी सदस्यों और सभी संबंधितों को 15 कार्य दिवसों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा और मामले पर विस्तृत दिशानिर्देशों को आयोग के आगामी बैठक में रखा जाएगा।

9.आगे, आयोग ने निर्णय लिया कि चूंकि भूमि और संपत्ति के निबटान का मामला उन संस्थाओं से संबंधित नहीं है जिन्होंने ग्रामाद्योग ऋण प्राप्त किया है, इसलिए ऐसी ग्रामोद्योगी संस्थाओं को सम्यक बंधक विलेखों, व्यक्तिगत गारंटी दस्तावेजों, बेबाकी प्रमाणपत्रों इत्यादि को वापस देने में कोई हिचकिचाहट नहीं की जानी चाहिए, जिन्होंने केवीआईसी को पूरी ऋण राशि वापस लौटा दी है।

10. आयोग ने संयुक्त सचिव, सू.ल.म.उ. के सुझावों पर विचार किया और फील्ड स्तर के कार्यालय के लिए उनके कार्यक्षेत्र में ऋण की वसूली करने तथा ऐसे आंशिक कार्यप्रदर्शन वाली अथवा गैर-कार्यनिष्पादन वाली सस्थाओं हेतु एक वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय लिया। कार्रवाई: निदेशक (खादी)

निदेशक (ग्रामोद्योग समन्वय)

2.मद संख्या 6(7) (643वीं बैठक का अनुलग्नक-I): आयोग के सदस्यों को उनके संबन्धित अंचल में आयोजित किए गए सरकारी कार्यक्रमों/समारोहों के बारे में जानकारी देना और इस प्रकार के समारोहों में भाग लेने के लिए आयोग के सदयों को आमंत्रित करना।

1.आयोग ने सदस्य (मध्य अंचल) के अवलोकन को नोट किया कि यद्यपि आयोग ने पूर्व में ऐसे निर्देश दिए थे कि आयोग के सदस्यों को उनके अधिकार क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों/समारोहों के बारे में जानकारी दी जाए, लेकिन फील्ड कार्यालयों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2.उन्होने यह भी सूचित किया कि कई राज्य/मंडलीय निदेशक प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों की स्वयं योजना बना लेते हैं और यहाँ तक उनमें माननीय मंत्रियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी उनमें आमंत्रित करते, लेकिन उसमें संबन्धित अंचल के सदस्य/उन-मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उसकी जानकारी नहीं देते हैं, जो की इस संबंध में आयोग द्वारा लिए गए निर्णय का पूरी तरह से उल्लंघन है।

3.इसलिए आयोग ने निर्णय लिया कि भविष्य में इस प्रकार के सभी चूककर्ता राज्य/मंडलीय निदेशकों के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। कार्रवाई: उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विपणन) उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)

निदेशक (विपणन)

****

न्यूज

hindustantimes
New Delhi, Monday, May 22, 2017

Charkha museum unveiled

New Delhi: The much-awaited heritage charkha museum and steel charkha was unveiled by BJP president Amit Shah on Sunday.

The charkha museum consists of 14 vintage charkhas in collaboration with Khadi and Village Industries Commission (KVIC).

KVIC chairman Vinai Kumar Saxena said that Charkha is a memorial to the unknown rural masses who took to the demonstrated ways of self-reliance and dignity of labour following the call of the father of the nation.

"The KVIC, in association with NDMC, has set up this museum, showcasing 50 to 100-year-old charkhas," he said. TNN

CP's charkha museum to spin ta

BJP president Amit Shah unveils a large steel charkha and heritage Charkha Museum

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

BJP president Amit Shah on Sunday unveiled a large steel charkha and heritage Charkha Museum — consisting 14 vintage charkhas — at Palika Bazar Park in Delhi's Connaught Place, amid much fervour and gaiety.

Hailing this initiative, Prime Minister Narendra Modi, in his special message to Khadi and Village Industries Commission (KVIC) chairman, said, "As Mahatma Gandhi himself believed, the Charkha is a symbol of our Swaraj and self-reliance. The museum and the monument for the charkha in the national Capital will be a proud tribute the charkha's historic importance in our nation. This will economically empower the lives of several weavers associated with the Khadi industry."

KVIC chairman Vinai KumarSaxena, in his welcome speech, said charkha, like the memorial to unknown soldiers, is memorial to the unknown rural masses, who took to ways of self-reliance and dignity of labour following the call of the Father of the nation.

"The KVIC, in association with New Delhi Municipal Corporation (NDMC), has set up this Heritage Charkha Museum, showcasing 50 to 100 years old charkhas, gifted to KVIC by the owners of these charkhas. The charkha, run by the PM on Oct 18, 2016 at Ludhiana, has also been kept permanently in the museum for display for general public," he said, adding, "Located in the heart of the city, it will certainly catch the eyes of foreign tourists coming here. The sparkling white marble statue of Mahatma Gandhi and the large steel charkha will be visible from all four sides of Baba Kharak Singh Marg."

Amit Shah unveils 12-ft tall Charkha, museum at CP

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: BJP national president Amit Shah on Sunday unveiled the Large Steel Charkha and Heritage Charkha Museum – consisting 14 vintage charkhas – at Palika Bazar Park in Delhi's Connaught Place, amid much fervour and gaiety.

Hailing the initiative, Prime Minister Narendra Modi, in a special message to Khadi and Village Industries Commission (KVIC) chairman, said: "As Mahatma Gandhi himself believed, the Charkha is a symbol of our Swaraj and self-reliance."

"The museum and the monument for the Charkha in the national Capital will be a proud tribute to the Charkha's historic importance in our nation. This will economically empower the lives of several weavers associated with the Khadi industry," the Prime Minister's message stated.

Meanwhile, Shah said that since time immemorial, the Charkha had been a "symbol of economic empowerment of our nation."

BJP national president Amit Shah at the throws open the Heritage Charkha Museum in Connaught Place on Saturday PC/PTI

"It is really a commendable job on the part of KVIC and NDMC (New Delhi Municipal Council) that both organisations have come up with a novel mission with an economic model to promote tourism. I hope that the spinning wheel would symbolise the mission of our Prime Minister Narendra Modi's 'Make in India'."

Mirroring similar views, Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprised Kalraj Mishra said that the Charkha would script the story of economic indipendence of India in coming days.

NDMC Chairperson Naresh Kumar said that the Charkha not only symbolises the vision of the New Delhi area, but also preserves the valuet and rich heritage of India's composite culture.

various agencies, including the Public Works Department, the three municipal corporations, Delhi Cantt, Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), and the New Delhi Municipal Council (NDMC), among others. It will be headed by the PWD Secretary.

A top government official said the committee has prepared a plan to desilt by June 15 all 163 major drains in the city, which cause massive waterlogging every monsoon.

The committee will coordinate the desilting work among the different agencies so that they don't end up passing the buck among each other, he said. "The committee has asked all agencies concerned to come up with their detailed plans on the removal of silt from drains and nalas by May 26, and also report how many drains they have been desilted so far," the official told PTI.

The PWD is in charge of 1,266 kms of roads in the capital while the rest fall under the jurisdiction of the three MCDs.

According to the India Meteorological Department (IMD), the normal monsoon onset date in the national Capital is June 28.

आदित्य बिर्ला फॅशनची खादी नाममुद्रा सादर

व्यापार प्रतिनिधी, मुंबई

आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड आणि खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने दोन महत्त्वाच्या भारतीय नाममुद्रेमधील बंध मजबूत करण्यासाठी धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली.

हा उपक्रम 'खादी फॉर फॅशन' आणि हातमागाच्या कापडाचा प्रसार करण्याच्या स्वप्नाला अनुसरून असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

याबाबतचा संमती करारनामा अंशू सिन्हा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केव्हीआयसी आणि आशिष दीक्षित, बिझनेस हेड, आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल लिमिटेड यांच्यामध्ये विनय कुमार सक्सेना, अध्यक्ष, केव्हीआयसी आणि इतरांच्या उपस्थितीत यावेळी करण्यात आला.

Millenniumpost

Besides gifting 500 new model eight-spindle charkhas to women spinners of nine states, a live charkha demonstration was also held by women inmates of Tihar jail

Heritage Charkha Museum spin tales of Indian legacy

Re-Spinning History!

Raymond Limited - India's leading Textile and Apparel conglomerate, marking the launch of India's first branded Khadi label - 'Khadi by Raymond' at an event in Mumbai recently. This initiative is conceptualized under KVIC mark regulation Act and permits Raymond to promote the sale and marketing of Khadi or Khadi products of village industries or handicrafts and forge links with established marketing agencies.

FASHION LUST
Sochismita Mohanta
Nothing Haunts Us Like Fashion

Khadi - the word conjures up images of late Father of our Nation and the Swadeshi movement he led for freeing our country from the clutches of the Britishers. Hand spinning and hand weaving have been around for thousands of years, thus, making the craft of khadi ancient.

Khadi has seen the golden era - as well as the dark days. The darker days were due to increase in production of low-cost mill fabric due to industrialisation spurred demand for raw produce cotton rather than high-quality imports. The fabric owes its revival to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi. He was the one who saw its potential as a tool to bring self-reliant, independent and bringing villages back to life. In his words: 'The spinning wheel represents to me the hope of the masses. The masses lost their freedom, such as it was, with the loss of the Charkha. The Charkha supplemented the agriculture of the villagers and gave it dignity.'

The journey of Khadi witnessed a major struggle for maintaining a balance between tradition and modernity. While tradition was indispensable for the nation to sustain its legitimacy and preserve the culture, modern aspects of life could not be overlooked if the nation had to compete on a global scale. Khadi was thus redefined by its proponents who made the fabric distinct and also added an element of flexibility to the idea of Khadi for it to sustain itself.

Khadi stands for what's traditional, but every tradition has to undergo change to stay relevant. Khadi has seen a new wave of acceptance thanks to many fashion designers like Sabyasachi Mukherjee, Ritu Kumar and Rohit Bal, to name a few. Brands like 'Fab India' and 'Nature Alley' have made their name with khadi products. Even 'KVIC' has decided to take a time leap, appointing Ritu Beri as their advisor, who wishes to change khadi's image from boring to chic. Promoting khadi's organic and zero carbon footprint nature, going the e-commerce route, and partnering with non-khadi players like Raymonds are but a few welcome steps in this direction. Creation of new designs and products like denim, trousers, and T-shirts suited for youngsters have created vibrancy in the market. It is a versatile fabric. It has the unique property of keeping the wearer warm in winter as well as cool in summer season. This fabric has coarse texture and gets easily crumpled, therefore in order to keep it firm and stiff, starch is to be added. This fabric on washing is more enhanced thus the more you wash it, better the look. Khadi is not easily worn out for years together, at least for 4-5 years. Very attractive and designer apparel are made by doing handwork on these garments made from it.

Khadi cotton is required to be starched so that it does not get easily crumpled. It comes in many colors and is not harmful to the skin as synthetic fabrics. This cotton is very soothing in summer season as ample amount of air ventilation is there, it has the capacity to absorb moisture therefore it easily soaks the sweat and keeps the wearer cool and dry.

Khadi cotton comes in plain as well as in printed fabrics. The most common outfit of made from khadi cotton is the Kurta. Many types of apparel are manufactured from khadi cotton like saris, salwar suits, fabric scarves, western tops, shirts, trousers, skirts, handkerchief,etc. It is a very durable fabric. In khadi silk, the ratio of khadi and silk fabric is 50:50. This fabric requires dry cleaning. It shrinks about 3% after the first wash. It is quite an expensive fabric. Khadi silk provides a royal and rich look. The various types of apparels made from khadi silk are salwar kameez, kurta pajama, saris, dupattas, shirts, vest and jackets. Apparels like kurta, jacket, sari blouses requires lining to be given to ensure its longetivity.

WORTHY CAUSE

Gautam Singhania, CMD, Raymond Group with Sumitra Kulkarni Gandhi, granddaughter of Mahatma Gandhi during a fashion show to promote khadi in Mumbai on Thursday. — PTI

खादी के फैशन का जलवा

रेमंड खादी-ए स्टोरी रे-स्पन थीम पर फैशन शो का आयोजन मुंबई में किया गया। इस फैशन शो में बॉलीवुड से लेकर ग्लैमर जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने अपनी उपस्थिति से चार चांद लगाए।

रेमंड ग्रुप के सीएमडी गौतम सिंघानिया अपने परिवार के साथ।

फैशन शो के दौरान वरिष्ठ अभिनेता कबीर बेदी

RAYMOND KHADI SHOW

Mumbai: Gautam Singhania, CMD, Raymond Group during a fashion show with theme "Raymond Khadi - A Story Re-spun" in Mumbai.

न्यूज

पहल | कनॉट प्लेस में 12 फीट ऊंचे चरखे की चमक, स्टेनलेस स्टील के इस चरखे का वजन ढाई टन

चरखा म्यूजियम में मिलेगा साल 1912 का चरखा

नई दिल्ली, लोकसत्य

खादी ग्रामोद्योग आयोग व नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की ओर से दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के पालिका बाजार एरिया में संयुक्त रूप से अनूठी पहल की। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वावलंबन के प्रतीक गांधी चरखा का विशाल रूप प्रदर्शित किया। स्टेनलेस स्टील से बने इस चरखे को देखकर लोगों ने खूब तारीफ की। रविवार देर शाम को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने चरखे के साथ-साथ चरखा म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। 12 फीट ऊंचा और 25 फीट लंबे स्टेनलेस स्टील चरखे का वजन ढाई टन है जिसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है।

इस अवसर पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्रा, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री डा महेश शर्मा, खेल एवं युवा मामलों के राज्यमंत्री विजय गोयल, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह, नई दिल्ली लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी के अलावा खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना, पालिका परिषद चेयरमैन नरेश कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

तारीफ

12 फीट ऊंचा और 25 फीट लंबे स्टेनलेस स्टील चरखे का वजन ढाई टन है जिसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने खादी ग्रामोद्योग आयोग व एनडीएमसी दोनों की भूरि-भूरि प्रशंसा की की। उन्होंने कहा कि गांधी चरखा हमारे देश में आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान का भी प्रतीक है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि आने वाले दिनों में यह चरखा भारत की आर्थिक आजादी की नई इबारत लिखेगा।

500 महिला बुनकरों को बांटे चरखे

इस अवसर पर श्री शाह की 500 महिला बुनकरों को 70 लाख रुपये मूल्य के चरखा वितरित किये गए। यहीं तिहाड़ जेल की 10 महिला कैदियों ने चरखा परिचालन का लाइव प्रस्तुतिकरण किया। इस अवसर पर आयोग की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित एक फिल्म का प्रदर्शन तथा इससे संबंधित एक डाक टिकट प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि खादी कातन की किफायत पर मर मिट जाने वाले उन शहीदों की तरह हजारों ग्रामीणों का भी प्रतिनिधित्व करता है जो महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वावलंबन और श्रमिकों की प्रतिष्ठा के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े।

चरखा म्यूजियम में यह है खास

खादी ग्रामोद्योग आयोग ने पालिका परिषद के साथ मिलकर जो हैरिटेज चरखा म्यूजियम स्थापित किया है इसमें 50 से 100 साल पुराने चरखों को संजो कर रखा गया है। यह सभी चरखे इनके मालिकों की ओर से म्यूजियम को गिफ्ट स्वरूप दिये गये है। इनमें से एक सबसे पुराना चरखा 1912 का है।

दिल्ली

आज का दिन

दिन में रात

कनॉट प्लेस में रविवार शाम 4 बजे अंधेरा छा गया। यहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने स्टील के चरखे का उद्घाटन किया। • इनाम

जागरण

स्वावलंबन का प्रतीक गांधी चरखा का विशालतम रूप

चरखे की चमक देख हुए चकित

गांधी चरखा हमारे देश में आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक रहा है : अमित शाह

राजधानी 3

दिल्ली में 37 हजार तेज रफ्तार वाहनों पर ठोंका गया जुर्माना

न्यूज

KVIC का जेल में शहद उत्पादन

कार्यालय संवाददाता

मुंबई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हनी मिशन और स्किल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने जेल में सजा काट रहे कैदियों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया .आयोग ने तिहाड़ जेल में 500 मधुमक्खियों के बक्सों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता का शहद उत्पादन करने की योजना बनाई है. आयोग के अध्यक्ष श्री वी के सक्सेना ने कहा कि तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए मधुमक्खी पालन पर पांच दिनों की कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसमें 20 से 25 वर्ष के 50 कैदियों को प्रशिक्षित किया गया.

■ सक्सेना ने कहा कि शिविर में मधुमक्खी पालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया. शहद उत्पादन की बारीकियां को युवाओं को समझाई गई.

■ सक्सेना ने कहा कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आयोग जेल परिसर में मधुमक्खियों का 500 बक्से रखेगा. इनके माध्यम से प्रतिवर्ष 12500 किलोग्राम शहद और 300 कि.ग्रा. मोम का उत्पादन होगा. प्रशिक्षण पूरा कर कैदी जेल से रिहा होने के बाद आसानी से रोजगार हासिल कर सकते हैं.

राष्ट्रपति भवन में होगा शहद का उत्पादन

केवीआईसी ने शुरू किया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

कार्यालय संवाददाता

मुंबई. खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग (केवीआईसी) ने राष्ट्रपति भवन के मालियों के लिए मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है. पाठ्यक्रम के माध्यम से आयोग ने राष्ट्रपति भवन में शहद उत्पादन की योजना बनाई है. राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में बड़ी संख्या में आम, जामुन , नीम और सहजन के पेड़ हैं. राष्ट्रपति भवन के मालियों को प्रशिक्षित कर केवीआईसी परिसर में 500 से अधिक मधुमक्खियों के (बॉक्स)छत्तों को स्थापित करेंगी. प्रशिक्षित माली शहद निकालने का काम करेंगे.

मालियों को लेकर योजना

केवीआईसी के अध्यक्ष वी.के.सक्सेना ने कहा कि इस मधुमक्खी पालन परियोजना में हर साल 12,500 किलो शहद तथा 300 किलो मोम का उत्पादन किया जा सकेगा. इसी के साथ राष्ट्रपति भवन के आसपास फूल, फल और फसल की उपज में भी 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.

सक्सेना के अनुसार भविष्य में आयोग ने नयी दिल्ली नगर निगम के सहयोग से राजधानी में 5,000 मधुमक्खी के बॉक्स लगाने की योजना तैयार की है.बॉक्स बाग़ान, लोधी गार्डन, तालकटोरा गार्डन और नेहरू पार्क सहित दिल्ली के विभिन्न बगानों के अलावा दिल्ली के विभिन्न आरक्षित वनों में लगाये जायेंगे.शहद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और खून को साफ करता है.

26

Powercracy

Charkha push for economic empowerment

By **Mail Today Bureau**
in New Delhi

IN A first, to link the *charkha* with tourism, BJP president Amit Shah on Sunday unveiled the Large Steel Charkha and Heritage Charkha Museum — consisting 14 vintage *charkhas* — at Palika Bazar Park in Delhi's Connaught Place.

Hailing this initiative, Prime Minister Narendra Modi, in a message to Khadi and Village Industries Commission (KVIC) chairman, said, "As Mahatma Gandhi himself believed, the *charkha* is a symbol of our *swaraj* and self-reliance. The museum and the monument for the *charkha* in the capital will be a proud tribute to the *charkha*'s historic importance in our nation. This will economically empower the lives of several weavers associated with the Khadi industry."

KVIC chairman Vinai Kumar Saxena, said that the *charkha*, like the memorial to unknown soldiers, is memorial to the rural masses, who look to the demonstrated ways of self-reliance and dignity of labour. "The KVIC, in association with New Delhi Municipal Corporation (NDMC), has set up this Heritage Charkha Museum, showcasing 50 to 100 year old *charkhas*, gifted to KVIC by the owners of these *charkhas*. The *charkha*, run by the PM on October 18, 2016 at Ludhiana, has also been kept permanently in the museum on display for the general public," he said, adding, "Located in the heart of the Capital, it will certainly be a tourist spot. The white marble statue of Mahatma Gandhi and the Large Steel Charkha will be visible from all four sides of Baba Kharak Singh Marg."

BJP President Amit Shah said that the *charkha* had always been the symbol of economic empowerment of our nation. "The KVIC and NDMC have come up with an economic model to promote tourism. I hope that the spinning wheel will symbolise the mission of Modi's 'Make in India'."

NDMC chairperson Naresh Kumar said, "*Charkha* is not only a symbol of simplicity and economic freedom by Swadeshi but also a symbol of peace and harmony," he said, adding, "The NDMC will deliver its best for the upkeep and maintenance of the Charkha and Heritage Museum. The Council is striving hard for transforming the efficient, effective and livable New Delhi area through the intervention of modern digital technology."

The 2.5-tonne large steel *charkha* is made of high-quality chromium nickel stainless steel and is corrosion resistant, non-magnetic and not hardened by heat. The order to make this 12 feet tall and 25 feet long spinning wheel was given to Prayog Samiti, KVIC unit, near Sabarmati Ashram in Gujarat. The high quality stainless steel for the *charkha* was donated by Steel Authority of India (SAIL).

Besides gifting 500 new model eight-spindle *charkhas* — with a cost of approximately ₹20 lakh — to the women spinners of nine states, a live charkha demonstration was also held by 10 women inmates of Tihar Jail. A film on Mahatma Gandhi was also screened, after a philatelic exhibition on 'Father of the Nation'.

BJP president Amit Shah with Union MSME minister Kalraj Mishra watching a live *charkha* demonstration by Tihar Jail inmates.

500 new model eight-spindle *charkhas* were gifted to women spinners of nine states

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शुक्रवार, 12 मई 2017

कॉर्पोरेट C

कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े लोगों को अपने पाठकों से रू-ब-रू कराने की पहल एनबीटी ने
कॉर्पोरेट गतिविधियों को सामने लाएगा। संबंधित व्यक्ति या समूह अपनी विशेष गतिविधि
porateconnect@gmail.com पर भेज सकते हैं। सुनिंदा गतिविधियों को एनबीटी

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने तिहाड़ में मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। हनी मिशन के तहत 50 कैदियों को स्वीट इकॉनमी में स्किल डिवेलपमेंट के बारे जानकारी दी गई। इस अवसर पर केवीआईसी के अध्यक्ष वी. के. सक्सेना और तिहाड़ के सदस्य उपस्थित रहे।

खादी-ग्रामोद्योग उत्पादों ने तोड़ा बिक्री का रेकॉर्ड

■ बिज़नेस डेस्क: आम तौर पर ग्रामीण उद्योगों और खादी इकाइयों को बहुत बड़ा नहीं माना जाता, लेकिन पिछले साल इन दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। ग्रामीण उत्पादों और खादी की बिक्री पहली बार 50,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई। खादी की बिक्री बढ़ाने पर सरकार भी खास जोर दे रही है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ग्रामीण उद्योगों में तैयार शहद, साबुन, पापड़ के सामान, फर्नीचर और जैविक खाद्य सामग्रियों की मांग में भारी तेजी देखने को मिली है। खास बात यह है कि कई ग्रामीण उद्योगों का संचालन महिलाएं कर रही हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के जुटाए आंकड़े बताते हैं कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 24% बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गई। इसी तरह, खादी उत्पादों की बिक्री भी 33 प्रतिशत बढ़कर 2,005 करोड़ रुपये तक पहुंच गई जो वित्त वर्ष 2015-16 में 1,635 करोड़ रुपये थी। बिक्री के मामले में तो खादी एवं ग्रामोद्योग ने तो रोजमर्रा के सामान बनानेवाली देश की कई कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। अकेले खादी की बिक्री भी बॉम्बे डाइंग और रेमंड जैसे मशहूर ब्रैंड से मुकाबला कर रही है।

हालांकि, इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2016-17 के अपने आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है। अब आयोग का लक्ष्य खादी की बिक्री वित्त वर्ष 2018-19 तक दोगुनी कर 5,000 करोड़ रुपये करने की है।

न्यूज

hindustantimes

Raymond

Fabindia and Raymond stores to sell 'Khadi' apparel

Soon, you would be able to buy ready-made apparel under the Khadi brand at Fabindia and Raymond outlets.

Raymond, KVIC launch India's first branded Khadi label

Posted, 2016-12-06

Newstrack India (http://newstrackindia.com/newsdetails/2016/12/06/306-Raymond-KVIC-launch-India-s-first-branded-Khadi-label-.html)

Report rights infringement

Mumbai (https://wn.com/Mumbai), Dec 6 (https://wn.com/Dec_6) (IANS (https://wn.com/IANS)) The Khadi & Village Industries (https://wn.com/Village_Industries) Commission (https://wn.com/Commission) and Raymond Ltd (https://wn.com/Raymond_Ltd), have joined hands to launch India (https://wn.com/India)'s first branded Khadi label as part of a strategic marketing initiative for the product from February 2017 (https://wn.com/February_2017), it was

> *"Spinning the 'charkha' has always been a symbol of self-reliance and now Raymond has Khadi, a true Indian fabric as part of its product portfolio. It will create multiple employment opportunities and empower artisans, especially the women, in rural areas,"*

CIRRUS

Raymond Stitches Up a Partnership with Khadi Commission

Neha.Tyagi
@timesgroup.com

Mumbai: Fabric and apparel major Raymond has partnered Khadi and Village Industries Commission (KVIC) to introduce a new line of clothing under the brand Khadi by Raymond, which will directly compete with Fabindia.

KVIC will certify Raymond to use Khadi mark to sell ready-made garments and fabric which will be available at KVIC and Raymond outlets across the country.

"Khadi is looking for an economic revolution and Raymond has technical expertise as well as significant global presence. This is a perfect match," said Sanjay Behl, CEO Raymond.

"Our idea was really to own the complete value chain by getting directly into the source of Khadi in India and the most widest and proficient in Khadi is KVIC," he added.

The initiative is taken under the KVIC Act that permits it to promote the sale and marketing of Khadi or products of village industries or handicrafts and forge links with established marketing agencies.

CIRRUS

CIRRUS

Economic Times - Mumbai;Wed, 07 Dec-16;Size : 80.58 sq.cm.;Page : 7

Raymond Partners Khadi for New Clothing Line

Our Bureau

Mumbai: Fabric and apparel major Raymond has partnered Khadi and Village Industries Commission (KVIC) to introduce a new line of clothing under the brand Khadi by Raymond, pitted directly against Fabindia, which is a leader in ethnic Indian clothing and fabrics.

KVIC will certify Raymond to use the Khadi mark to sell ready-made garments and fabric, which will be available at KVIC and Raymond outlets across the country.

"Khadi is looking for a economic revolution ar Raymond has technical e pertise as well as significa global prese ce", said Sa jay Behl, CE Raymond.

"Our idea wa to own th complete value chain by ge ting directly into the sour of Khadi in India and th most widest and proficie in Khadi is KVIC."

The initiative is under th aegis of the KVIC Act 1956.

Khadi industry to employ 5 cr people in 5 years: Giriraj

MUMBAI: The Ministry of Medium, Small and Micro Enterprises (MSME) has a target to employ around five crore people through the khadi industry over the next five years, Union minister Giriraj Singh has said.

"We have made a plan to introduce solar-run spinning wheels in KVIC (Khadi and Village Industries Commission) so that it can provide employment to over five crore people throughout the nation in the next five years," Singh told PTI here on Thursday.

The Union Minister of State for MSME was speaking here on the sidelines of an event, 'Khadi by Raymond'.

"Presently khadi is less than one per cent of textiles, but due to concerted efforts in the last two years, the khadi industry sales have gone up from Rs 35,000 crore in 2014 to about Rs 52,000 crore," he said.

The MSME ministry is taking various steps to boost the KVIC. Along with coir industry, the khadi industry is on top of the ministry's agenda, Singh said.

"Various schemes, including interest subsidies, financial assistance under the market promotion and development scheme, cluster-based development opportunities, as well as design-oriented public private partnerships, are being promoted by the ministry," he said.

The KVIC has partnered with private players, including Arvind, Raymond and others, for joint promotion of the fabric. The aim is to popularise and boost the use of khadi, especially among the youth and corporates.

Singh said that fashion designers are also being involved for launching eco and user-friendly products.

"The new scheme of 'zero defect, zero effect', launched by the prime minister, will help increase the quality to match the global standards," he said.

KVIC is looking to promote khadi as a fashionable fabric and to open premium lounges in major cities, he said.

There are more than 7,000 showrooms of the KVIC which can be used as selling points of khadi products.

The ministry is also looking to expand the khadi stores network through more franchisees and tie-ups with partners for e-commerce sales, Singh said.

KVIC is also looking to digitise its systems to facilitate e-governance to reduce paperwork and save time, he said. PTI

Minister of State for MSME Giriraj Singh at the opening of 'Khadi by Raymond', India's first branded khadi label in Mumbai Thursday. He was the chief guest at the event. *Aishwarya Maheshwari*

One shouldn't hesitate to say 'Bharat Mata ki Jai' or buy khadi: Giriraj Singh

EXPRESS NEWS SERVICE
MUMBAI, MAY 18

ONE SHOULDN'T hesitate to say 'Bharat Mata ki Jai' and neither should one hesitate to buy khadi, according to Minister of State for Micro, Small and Medium Enterprises Giriraj Singh on Thursday.

Singh, who was in Mumbai to unveil Raymond Limited's khadi collection, said khadi, Gandhi, Modi and Raymond were now tied together through the convergence of the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) with Raymond Ltd.

"Gandhi's dream and Modi's dream to take khadi to the global market will not be fulfilled unless we take the entrepreneurial route," said Singh, adding that the benefit of the artisans should be at the heart of the initiative.

The ministry aims to generate over five crore jobs by 2022 in the khadi industry, he said. KVIC chairman Vinai Saxena said khadi has to be taken to the corporate level to make it a success. Sanjay Behl, CEO, Raymond Limited, said their venture will help create 2.7 lakh man hours of employment for artisans. Mahatma Gandhi's granddaughter Sumitra Kulkarni, too, was present on the occasion.

Khadi industry plans to employ 5 cr people in 5 yrs: Giriraj

Special Correspondent

Ministry of Medium, Small and Micro Enterprises (MSME) has a target to employ around five crore people through the khadi industry over the next five years, Union minister Giriraj Singh has said.

"We have made a plan to introduce solar-run spinning wheels in KVIC (Khadi and Village Industries Commission) so that it can provide employment to over five crore people throughout the nation in the next five years," Singh said.

The Union Minister of State for MSME was speaking here on the sidelines of an event, 'Khadi by Raymond'.

"Presently khadi is less than one per cent of textiles, but due to concerted efforts in the last two years, the khadi industry sales have gone up from Rs 35,000 crore in 2014 to about Rs 52,000 crore," he said.

The MSME ministry is taking various steps to boost the KVIC. Along with coir industry, the khadi industry is on top of the ministry's agenda, Singh said.

"Various schemes, including interest subsidies, financial assistance under the market promotion and development scheme, cluster-based development opportunities, as well as design-oriented public private partnerships, are being promoted by the ministry," he said.

The KVIC has partnered with private players, including Arvind, Raymond and others, for joint promotion of the fabric.

The aim is to popularise and boost the use of khadi, especially among the youth and corporates.

Singh said that fashion designers are also being involved for launching eco and user-friendly products.

"The new scheme of 'zero defect, zero effect', launched by the prime minister, will help increase the quality to match the global standards," he said.

KVIC is looking to promote khadi as a fashionable fabric and to open premium lounges in major cities, he said.

There are more than 7,000 showrooms of the KVIC which can be used as selling points of khadi products.

The ministry is also looking to expand the khadi stores network through more franchisees and tie-ups with partners for e-commerce sales, Singh said.

KVIC is also looking to digitise its systems to facilitate e-governance to reduce paperwork and save time, he said.

Man commits suicide hours prior to his wedding in Nashik

Special Correspondent

A 26-year-old man allegedly committed suicide hours before his wedding ceremony in the district, police said.

Prashant Namdev Khairnar, who worked as a junior engineer in a Nashik-based firm, was scheduled to get married yesterday.

However, just a few hours before the wedding was to be solemnised, Prashant hanged himself from the ceiling at his house in Pimpalgaon-Wakhari village of the district, an official at Devala police station said.

Police were yet to ascertain the reason behind suicide.

The Devala police registered a case in this connection.

The mans body was handed over to his family members after a postmortem was done at Devala rural hospital.

raymond

न्यूज

खादीचे ब्रॅण्डेड उत्पादन

रेमंडस् या आघाडीच्या ब्रॅण्डने खादी वस्त्रोद्योगात प्रवेश करीत 'खादी बाय रेमंड' हे नवीन लेबल प्रस्थापित केले आहे. या कलेक्शनमध्ये हिंदुस्थानी संस्कृती आणि पारंपरिक खादी कपड्यांसह रेमंडच्या शाही परंपरेला आणि नव्या पिढीच्या निवडीला साजेसे रेडीमेड कपडे तसेच शिलाईसाठी खादीचे नुसते कापड उपलब्ध होणार आहे. पंतप्रधानांच्या मेक इन इंडिया अभियानाला पाठिंबा देण्याच्या हेतूने खादीला पुढे आणण्यासाठी हे कलेक्शन तयार करण्यात आल्याचे रेमंड लिमिटेडचे अध्यक्ष गौतम सिंघानिया यांनी सांगितले.

BAPUJI'S KHADI NOW GOES MAINSTREAM

Textile and apparel conglomerate Raymond Ltd, headed by Gautam H Singhania, launched its first branded khadi label, with an aim to position it as a fashion fabric globally

GSTમાં બ્રાન્ડેડ અંગે સ્પષ્ટતાના અભાવે રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ ઉત્પાદકો વિમાસણમાં

નવીદિલ્હી, તા. ૨૦

નવી પદ્ધતિમાં તૈયાર કપડાં પર ૧૮ ટકા દર લાગુ કરાયો છે

அடுத்த 5 ஆண்டுகளில்

காதி துறையில் 5 கோடி வேலைவாய்ப்பு

● மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் தகவல்

கிரிராஜ் சிங்

2014-ம் ஆண்டு காதி விற்பனை ரூ. 35,000 கோடிக்கு நடந்துள்ளது. ஆனால் தற்போது ரூ.52,000 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

खादी उद्योग ५ साल में ५ करोड़ लोगों को देगा रोजगार- गिरिराज

मुंबई, सरकार की खादी उद्योग में अगले पांच साल के दौरान पांच करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने यह जानकारी दी। सिंह ने कल यहां पीटीआई-भाषा को बताया, 'हमने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग - (केवीआईसी) में सौर उर्जा से चलने वाले कताई चक्के लाने की योजना बनाई है ताकि इस क्षेत्र में अगले पांच साल के दौरान पांच करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।' केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री कल यहां 'रेमंड की खादी' कार्यक्रम के मौके पर अलग से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'इस समय खादी कुल कपड़ा उद्योग का एक प्रतिशत से भी कम है लेकिन पिछले दो साल के दौरान किये गये प्रयासों से खादी उद्योग का कारोबार 2014 के 35,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 52,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।' उन्होंने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठा रहा है। कयर उद्योग(नारियल के रेशे) के साथ साथ खादी उद्योग सरकार के एजेंडा में सबसे शीर्ष पर है। सिंह ने कहा, 'कई तरह की योजनायें जैसे कि ब्याज सहायता देना, बाजार उन्नयन और विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता, क्लस्टर आधारित विकास के अवसर और इसके साथ ही नये डिजाइनों को बढ़ावा देते हुये सार्वजनिक निजी भागीदारी योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।' खादी ग्रामोद्योग ने खादी कपड़ों के संयुक्त तौर पर संवर्धन के लिये निजी क्षेत्र की कंपनियों अरविंद, रेमंड और अन्य के साथ भी भागीदारी की है। इसके पीछे उद्देश्य खादी के कपड़ों को विशेषतौर पर युवाओं और कंपनियों के बीच प्रचलित करना है। सिंह ने कहा कि खादी के वातावरण अनुकूल और गुणवत्ता वाले कपड़ों को बाजार में उतारने के लिये फैशन डिजाइनरों को भी शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खादी कपड़ों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिये 'जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट' योजना को शुरू किया है। इससे खादी उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी।'

सिंह ने कहा कि केवीआईसी खादी को नये फैशन के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। उसने देश के प्रमुख शहरों में आधुनिक खादी कपड़ों के प्रीमियम लांज खोलने का भी फैसला किया है। देशभर में खादी कपड़ों के 7,000 से अधिक शो-रूम हैं जिनमें खादी उत्पादों की बिक्री की जा सकती है। एमएसएमई राज्य मंत्री ने कहा कि मंत्रालय खादी स्टोर नेटवर्क का विस्तार करने पर भी गौर कर रहा है। खादी उत्पादों की ई-कामर्स प्लेटफार्म के जरिये बिक्री के लिये भागीदारी और गठबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केवीआईसी अपने पूरे कामकाज का डिजिटलीकरण कराने पर भी ध्यान दे रहा है ताकि कागजी कार्य को कम से कम किया जा सके।

Raymond

न्यूज

'खादी बाय रेमंड' – भारतातील खादीचे पहिले ब्रॅण्डेड उत्पादन

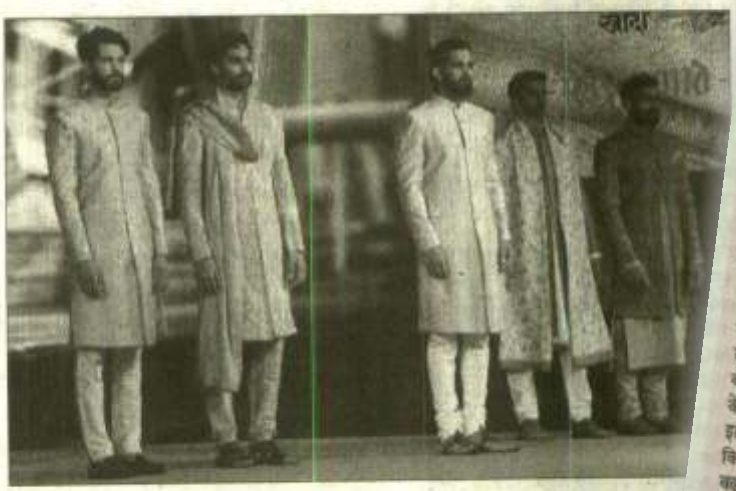

● मुंबई । प्रतिनिधी

रेमंड्स या भारतातल्या अग्रेसर ब्रॅण्डने मुंबईत साजऱ्या झालेल्या एका भव्य कार्यामात ही कंपनी प्रथमच खादी वस्त्रोद्योगात प्रवेश करत असल्याचे जाहीर केले असून त्यांनी 'खादी बाय रेमंड' हे नवीन लेबल प्रस्थापित केले आहे. या भव्य कार्यामाला प्रमुख पाहुणे म्हणून माननीय राज्यमंत्री (एमएसएमई - सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग) श्री. गिरीराज सिंग आणि विशेष अतिथी म्हणून महात्मा गांधी यांची नात माननीय सुमित्रा कुलकर्णी गांधी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सरकारचे कॅबीनेट मंत्री (उद्योग व खाणकाम) माननीय श्री. सुभाष देसाई, गुजरातचे कॅबिनेट मंत्री (शिक्षण विभाग) श्री. भुपेंद्रसिंह चुडासमा आणि केव्हीआयसीच्या सीईओ श्रीमती अन्शु सिन्हा तसेच, केव्हीआयसीच्या एफए श्रीमती उषा सुरेश उपस्थित होत्या.

भारतीय टिव्ही व चित्रपट क्षेत्रातील ज्येष्ठ अभिनेते कबीर बेदी आणि भारतीय चित्रपट अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी या दोघांनी या कार्यामाची संध्याकाळ संस्मरणीय केली असून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील 'खादी' चळवळीचे महत्व व त्याचा स्वावलंबन तत्वाशी असलेला संबंध विषद केला. 'खादी बाय रेमंड' या लेबलअंतर्गत येणाऱ्या कलेक्शनमध्ये भारतीय संस्कृतीशी मिळत्याजुळत्या, पारंपरिक खादी कपड्यांसह रेमंडच्या शाही परंपरेला व आधुनिक पिढीच्या निवडीला साजेसे रेडीमेड कपडे तसेच, शिलाईसाठीचे खादीचे नुसते कापडही उपलब्ध होणार आहे.

'खादी उद्योग से 5 करोड़ को मिलेगा रोजगार'

बिजनेस डेस्क : मीडियम, स्मॉल ऐंड माइक्रो एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) मिनिस्ट्री ने आने वाले पांच वर्षों में खादी उद्योग के द्वारा पांच करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह बात कही। उन्होंने गुरुवार को कहा, 'हमारी योजना केवीआईसी (खादी ग्रामोद्योग) में सौर ऊर्जा से चलने वाले कताई चक्के लाने की है। इससे अगले पांच सालों में देशभर में पांच करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।' उन्होंने कहा, 'मौजूदा समय में कुल कपड़ा उद्योग में खादी एक फीसदी से भी कम है। लेकिन बीते दो वर्षों में ठोस प्रयासों के चलते खादी उद्योग की सेल 35,000 करोड़ रुपये (2014 में) से बढ़कर 52,000 करोड़ रुपये हो गई है।' केंद्रीय राज्य मंत्री ने यहां एक कार्यक्रम से इतर यह बात कही। गिरिराज सिंह ने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है। कयर उद्योग (नारियल के रेशे) के साथ-साथ खादी उद्योग सरकार के अजेंडा में शीर्ष पर है। सिंह ने कहा, 'कई तरह की योजनाएं जैसे कि ब्याज सहायता देना, बाजार उन्नयन और विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता, क्लस्टर आधारित विकास के अवसर और इसके साथ ही नए डिजाइनों को बढ़ावा देते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। खादी ग्रामोद्योग ने खादी कपड़ों के संयुक्त तौर पर संवर्धन के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों अरविंद, रेमंड और अन्य के साथ भी भागीदारी की है। इसके पीछे उद्देश्य खादी के कपड़ों को विशेषतौर पर युवाओं और कामगारों के बीच प्रचलित करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खादी के वातावरण अनुकूल और गुणवत्ता वाले कपड़ों को बाजार में उतारने के लिए फैशन डिजाइनरों को भी शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी कपड़ों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए 'जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट' योजना को शुरू किया है। इससे खादी उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी।'

खादी ग्रामोद्योग ५ वर्षांमध्ये ५ कोटींना देणार रोजगार

मुंबई : खादी उद्योगाद्वारे येत्या ५ वर्षांमध्ये सुमारे ५ कोटी लोकांसाठी रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट असल्याची घोषणा केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग राज्यमंत्री गिरिराज सिंह यांनी शुक्रवारी येथे केली. खादी ग्रामोद्योग आयोगातर्फे (केव्हीआयसी) सौरऊर्जेवर चालणारी स्पिनिंग व्हील्स आम्ही बनवून त्याद्वारे ५ कोटी लोकांना देशभरात रोजगार निर्माण करून देणार असल्याची योजना तयार केली, असे त्यांनी सांगितले.

रेमंडद्वारा खादी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ते आले असता त्या वेळी ते बोलत होते. सध्या खादी वस्त्रोद्योगात एक टक्का कमी असून येत्या दोन वर्षांमध्ये त्या उद्योगावर लक्ष केंद्रित केल्याने ही स्थिती येऊ शकली आहे. खादीची विक्री वाढून २०१४ मध्ये ती ३५ हजार कोटी होती, ती ५२ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे, असेही त्यांनी सांगितले. खादी ग्रामोद्योगाला गतिमान करण्यासाठी काही उद्योगांबरोबरही विविध पावले उचलली जात आहेत. आपल्या मंत्रालयाने त्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, असे ते म्हणाले. व्याजात सवलत, बाजारपेठेच्या प्रमाणात अर्थसहाय्य, विकास योजना, क्लस्टर आधारित विकासाच्या संधी आणि सरकारी व खासगी उद्योगांच्या भागीदारीने विविध योजना आम्ही या खादी उद्योगाच्या विकासासाठी विकसित करत आहोत. अरविंद, रेमंड व अन्य खासगी उद्योगांच्या सहकार्याने संयुक्तपणे वस्त्रोद्योगात प्रोत्साहन देत आहोत. युवकांमध्येही खादीचा वापर वाढावा व लोकप्रिय व्हावा, हा त्यामागचा उद्देश आहे, असे सिंह यांनी सांगितले.

झीरो डिफेक्ट, झीरो इफेक्ट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झीरो डिफेक्ट, झीरो इफेक्ट ही नवी योजना सुरू केली असून त्यामुळे जागतिक दर्जाप्रत आपण पोहोचू. त्यात तशा दृष्टीने दर्जात्मक वाढ होईल, असा विश्वास सिंह यांनी व्यक्त केला.

७००० शोरूम्स

खादी ग्रामोद्योगाने विक्री प्रोत्साहनासाठी शोरूम्समध्येही वाढ केली असून आज खादीच्या शोरूम्सची संख्या देशभरात ७००० पेक्षाही अधिक झाली आहे. अजूनही खादी स्टोर्सच्या वितरणाच्या जाळ्यामध्ये वाढ करण्याचे व फ्रँचाईजी नेमण्याची योजना असल्याचे सांगत ई कॉमर्स विक्रीही वृद्धिंगत करण्याचे त्यांनी सांगितले.

हातेहात: मुम्बईये एक अनुष्ठाने रेमन्ड गोष्ठीर सिएमडि गौतम सिंहानियार सङ्गे गाँधीजिर नातनि सुमित्रा कुलकार्नि गाँधी ■ पिटिआई

ખાદી ઉદ્યોગ 5 વર્ષમાં 5 કરોડ રોજગારી આપશે : ગિરિરાજ સિંહ

ભાસ્કર ન્યૂઝ | મુંબઈ

ખાદી ઉદ્યોગ આગામી પાંચ વર્ષમાં 5 કરોડ લોકોને રોજગાર આપશે. ખાદી અને ગ્રામીણ ઉદ્યોગ પંચ (કેવીઆઈસી)માં સૌર ઊર્જા પર ચાલતા ચરખા લાવવાની અમારી યોજના છે, જેથી રાષ્ટ્રભરમાં આગામ પાંચ વર્ષમાં પાંચ કરોડથી વધુ લોકોને તેના થકી રોજગાર આપી શકાશે. ખાસ કરીને વૃદ્ધ અને અશક્ત મહિલાઓ આ સૌર ઊર્જા પર ચાલતા ચરખા પર આસાનીથી કામ કરી શકશે, એમ મધ્યમ, લઘુ અને સૂક્ષ્મ ઉદ્યોગ (એમએસએમઈ) મંત્રી ગિરિરાજ સિંહે જણાવ્યું હતું.

ખાદી સાથે રેમન્ડે સહયોગ સાધવાથી હવે તેનું કોર્પોરેટાઈઝેશન થયું છે. ખાદીનું વેચાણ 2014માં ₹. 35,000 કરોડ હતું, પરંતુ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખાદી અપનાવવા આપેલા ભાર અને અન્ય પગલાંઓને લીધે આ ઉદ્યોગ આજે આશરે ₹. 52,000 કરોડ સુધી પહોંચી ગયો છે. હવે ખાદીનું લેબલ મળતાં તેમાં ઓર વધારો થવાની આશા છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.

રેમન્ડ લિમિટેડે ભારતનું પ્રથમ બ્રાન્ડેડ ખાદી લેબલ ખાદી બાય રેમન્ડ મુંબઈમાં એક ભવ્ય સમારંભમાં લોન્ચ કર્યું તે સમયે તેઓ બોલતા હતા. આ સમયે સન્માનનીય અતિથિ તરીકે મહાત્મા ગાંધીનાં પૌત્રી સુમિત્રા કુલકર્ણી - ગાંધી હાજર હતાં. અન્યોમાં ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગના કેબિનેટ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, કેવીઆઈસીના સીઈઓ અંશુ સિંહા, કેવીઆઈસીના એક્ઝે ઉષા સુરેશ અને અન્ય માનવંતા મહેમાનો હાજર હતા.

આ કાર્યક્રમમાં ગૌતમ સિંઘાણિયાએ સુમિત્રા કુલકર્ણી- ગાંધીનુ ખાદીની શાલ આપીને સન્માન કર્યું હતું.

રેમન્ડ લિમિટેડના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર શ્રી ગૌતમ હરી સિંઘાણિયાએ જણાવ્યું હતું કે દેખીતી રીતે જ ખાદી ધરાવવી તે ગૌરવની વાત છે. આપણા રાષ્ટ્રનું આ વસ્ત્ર અમારા પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયોનો હવે હિસ્સો છે. અમુક નવા ડિઝાઈન પ્રવાહો અને તેના ગુણવત્તાયુક્ત રેમન્ડ ખાદી પસંદગીના વસ્ત્ર તરીકે નવી ઊંચાઈ સર કરવા સુસજ્જ છે.

કેવીઆઈસીના ચેરમેન વી કે સકસેનાએ જણાવ્યું હતું કે આ ઐતિહાસિક અવસરે શ્રેષ્ઠ નિષ્ણાતો ખાદી સાથે સંકળાવા માટે એકત્ર આવ્યા છે.

पांच साल में पांच करोड़ रोजगार

मुंबई। सरकार की खादी उद्योग में अगले पांच साल के दौरान पांच करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने यह जानकारी दी। सिंह ने बताया कि हमने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) में सौर ऊर्जा से चलने वाले कताई चक्के लाने की योजना बनाई है ताकि इस क्षेत्र में अगले पांच साल के दौरान पांच करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री रेमंड की खादी कार्यक्रम के मौके पर अलग से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समय खादी कुल कपड़ा उद्योग का एक प्रतिशत से भी कम है, लेकिन पिछले 2 साल के दौरान किए गए प्रयासों से खादी उद्योग का कारोबार 2014 के 35,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 52,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठा रहा है। कयर उद्योग के साथ साथ खादी उद्योग सरकार के एजेंडा में सबसे शीर्ष पर है। सिंह ने कहा कि कई तरह की योजनाएं जैसे कि ब्याज सहायता देना, बाजार उन्नयन और विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता, क्लस्टर आधारित विकास के अवसर और इसके साथ ही नए डिजाइनों को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

खादी बाय रेमंड; खादीचे पहिले ब्रॅण्डेड उत्पादन

प्रतिनिधी

मुंबई:- रेमंड्स या भारतातल्या अग्रेसर ब्रॅण्डने मुंबईत साजऱ्या झालेल्या एका भव्य कार्यक्रमात ही कंपनी प्रथमच खादी वस्त्रोद्योगात प्रवेश करत असल्याचे जाहीर केले असून त्यांनी खादी बाय रेमंड हे नवीन लेबल प्रस्थापित केले आहे. या भव्य कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्यमंत्री (एमएसएमई-सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग) गिरीराज सिंग आणि विशेष अतिथी म्हणून महात्मा गांधी यांची नात सुमित्रा कुलकर्णी-गांधी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सरकारचे कॅबीनेट मंत्री (उद्योग व खाणकाम) सुभाष देसाई, गुजरातचे कॅबिनेट मंत्री (शिक्षण विभाग), भूपेंद्रसिंह चुडासमा आणि केव्हीआयसीच्या सीईओ श्रीमती अन्शु सिन्हा तसेच, केव्हीआयसीच्या एमए श्रीमती उषा सुरेश उपस्थित होत्या. भारतीय टिव्ही व चित्रपट क्षेत्रातील ज्येष्ठ अभिनेते कबीर बेदी आणि भारतीय चित्रपट अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी या दोघांनी या कार्यक्रमाची संध्याकाळ संस्मरणीय केली असून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील खादी चळवळीचे महत्त्व व त्याचा स्वावलंबन तत्त्वाशी असलेला संबंध विषद केला.

न्यूज

खादी उद्योगात येत्या ५ वर्षांत ५ कोटी लोकांना देणार रोजगार - गिरीराज सिंग

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योग राज्यमंत्री गिरीराज सिंग यांनी सांगितले की, खादी उद्योगात येत्या पाच वर्षांत ५ कोटी लोकांना रोजगार देण्याची योजना सरकारने हाती घेतली आहे.

गिरीराज सिंग यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की, खादी आणि ग्रामोद्योगात सौर ऊर्जेवर चालणारे चरखे आणण्याची योजना आम्ही आखली आहे. त्यातून येत्या पाच वर्षांत पाच कोटी लोकांना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

येथे 'रेमंडची खादी' या कार्यक्रमानिमित्त गिरीराज सिंग येथे आले होते. त्यानिमित्त त्यांनी वृत्तसंस्थेशी बातचीत केली. त्यांनी सांगितले की, सध्या कापड उद्योगात खादीच्या कापडाचा हिस्सा एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे; मात्र गेल्या दोन वर्षांत करण्यात आलेल्या प्रयत्नांमुळे खादी उद्योगाचा व्यवसाय ५२ हजार कोटींवर गेला आहे. २०१४ मध्ये तो ३५ हजार कोटी रुपये होता. आपले मंत्रालय खादी ग्रामोद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रकारची पावले उचलत आहे. काथ्या (नारळाच्या शेंड्या) उद्योगासह खादी उद्योग सरकारच्या अजेंड्यावर शीर्षस्थानी आहे.

गिरीराज सिंग यांनी सांगितले की, व्याज सवलत, बाजार प्रोत्साहन आणि विकास योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत, क्लस्टर आधारित विकासाच्या संधी आणि नव्या डिझाईनला प्रोत्साहन देतानाच सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहित केले जात आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी उपक्रमांतर्गत अरविंद, रेमंड आणि अन्य मोठ्या उद्योगांशी भागीदारी करण्यात आली आहे. तरुण आणि उद्योग जगतात खादी लोकप्रिय करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.

गिरीराज सिंग यांनी म्हटले की, पर्यावरणपूरक, तसेच वापरस्नेही उत्पादने तयार करण्यासाठी फॅशन डिझायनरांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे. पंतप्रधानांनी नुकतीच 'झीरो डिफेक्ट, झीरो इफेक्ट' योजना सुरु केली आहे. त्यातून खादीचा दर्जा जागतिक पातळीचा होईल. खादीला फॅशनचा दर्जा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आपल्या मंत्रालयाच्या ७ हजार शोरूमचा वापर विक्री केंद्रे म्हणून करण्यात येईल.

मुंबई : रेमंड समूहाने खादी क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. यासंबंधात झाले कार्यक्रमाला कंपनीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक गौतम सिंघानिया अ महात्मा गांधी यांच्या नात सुमित्रा कुलकर्णी गांधी उपस्थित होत्या.

खादी उद्योग से 5 करोड़ को मिलेगा रोजगार

कार्यालय संवाददाता

मुंबई. मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ने आने वाले पांच वर्षों में खादी उद्योग के द्वारा पांच करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह बात कही. उन्होंने कहा, हमारी योजना केवीआईसी में सौर ऊर्जा से चलने वाले कताई चक्के लाने की है. इससे अगले पांच सालों में देशभर में पांच करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके. उन्होंने कहा, 'मौजूदा समय में कुल कपड़ा उद्योग में खादी एक फीसदी से भी कम है. लेकिन बीते दो वर्षों में ठोस प्रयासों के चलते खादी उद्योग की सेल 35,000 करोड़ रुपये (2014 में) से बढ़कर 52,000 करोड़ रुपये हो गई है. केंद्रीय राज्य मंत्री ने यहां एक कार्यक्रम से इतर यह बात कही. एमएसएमई मंत्रालय खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है. कयर उद्योग के साथ-साथ खादी उद्योग सरकार के एजेंडा में शीर्ष पर हैं. सिंह ने कहा, कई तरह की योजनाएं जैसे कि ब्याज सहायता देना, बाजार उन्नयन और विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता, क्लस्टर आधारित विकास के अवसर और इसके साथ ही नए डिजाइनों को बढ़ावा देते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है.

52,000 करोड़ रुपये तक पहुंची सेल

7,000 से अधिक शोरूम देशभर में

■ खादी ग्रामोद्योग ने खादी कपड़ों के संयुक्त तौर पर संवर्धन के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों अरविंद, रेमंड और अन्य के साथ भी भागीदारी की है. इसके पीछे उद्देश्य खादी के कपड़ों को विशेषतौर पर युवाओं और कंपनियों के बीच प्रचलित करना है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खादी के वातावरण अनुकूल और गुणवत्ता वाले कपड़ों को बाजार में उतारने के लिए फैशन डिजाइनरों को भी शामिल किया जा रहा है.

■ उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खादी कपड़ों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए "जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट" योजना को शुरू किया है. इससे खादी उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी. सिंह ने कहा कि केवीआईसी खादी को नए फैशन के साथ आगे बढ़ाना चाहती है.

■ उसने देश के प्रमुख शहरों में आधुनिक खादी कपड़ों के प्रीमियम लाउंज खोलने का भी फैसला किया है. देशभर में खादी कपड़ों के 7,000 से अधिक शोरूम हैं जिनमें खादी उत्पादों की बिक्री की जा सकती है. एमएसएमई राज्य मंत्री ने कहा कि मंत्रालय खादी स्टोर नेटवर्क का विस्तार करने पर भी गौर कर रहा है.

■ खादी उत्पादों की ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिए बिक्री के लिए भागीदारी और गठबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि केवीआईसी अपने पूरे कामकाज का डिजिटलीकरण कराने पर भी ध्यान दे रहा है ताकि कागजी काम को कम से कम किया जा सके.

न्यूज

09/12/2016 Raymond, KVIC launch India's first branded Khadi label - Daily World

Raymond, KVIC launch India's first branded Khadi label

Daily finance

Mumbai, Dec 6 : The Khadi & Village Industries Commission and Raymond Ltd. have joined hands to launch India's first branded Khadi label as part of a strategic marketing initiative for the product from February 2017, it was announced here on Tuesday.

By this, KVIC will permit Raymonds to use the Khadi Mark, branded as 'Khadi by Raymond' and the latter will source all its Khadi requirements from stores in Mumbai and Delhi.

Besides positioning Khadi as a "fashion fabric" globally, the initiative is expected to generate incremental employment of around 2.10 lakh man-hours for spinners and weavers.

'Khadi by Raymonds' will hit the stores at KVIC outlets and Raymond shops across the country from February 2017 and also be available online.

The agreement was signed between KVIC CEO Usha Suresh and Raymond Ltd CEO Sanjay Behl in the presence of KVIC Chairman Vinai Kumar Saxena and Raymond Ltd Chairman & Managing Director Gautam Hari Singhania.

Terming it as a historic partnership between KVIC and Raymond for value-added marketing of Khadi, Saxena said its in tune with the Make in India initiative and help bridge the rural-urban industry divide.

"Spinning the 'charkha' has always been a symbol of self-reliance and now Raymond has Khadi, a true Indian fabric as part of its product portfolio. It will create multiple employment opportunities and empower artisans, especially the women, in rural areas," said Singhania.

Suresh said by this partnership, Khadi would be promoted as a global and fashionable fabric and Raymond will provide a khadi niche among the fashion conscious global Indians who love genuine hand-spun fabric.

In view of evolving trends of customers' preferences, Behl said through the partnership, Raymond will promote Khadi globally and offer a wide array of fabric blends and garments spanning suits, jackets, shirts, trousers in tune with international design and quality trends.

IANS

KVIC, Raymond join hands to launch Khadi label

Khadi & Village Industries Commission (KVIC), part of the MSME ministry, and apparel major Raymond today announced a joint initiative to market the khadi fabric to position it as a fashion trend. Raymond will be sourcing all India variety of khadi from KVIC departmental sales outlets from Delhi and Mumbai, for over the counter sales as well as crafting readymade garments for its apparel brands. PTI

6/6/2017 ABFRL and KVIC joins hand to launch 'Khadi by Peter England', Retail News, ET Retail

☰ NEWS SITES Sign in/Sign up

NEWS UPDATE
Parle Products soon to enter pulses category
READ MORE

An initiative of The Economic Times

Home | News | IndustrySpeak | Jobs & Career | Feature | Data & Analytics | Brand Solutions

Apparel & Fashion | E-commerce | Food & Entertainment | CDIT | Health & Beauty | Home & Decor | Books and Stationery | Industry

Retail News / Latest Retail News / Apparel & Fashion / Apparel

Apparel & Fashion » Apparel » Peter England KVIC outlets ABFRL

ABFRL and KVIC joins hand to launch 'Khadi by Peter England'

As a part of this partnership, Peter England will be among the brands to develop an exclusive product line product line branded as 'Khadi by Peter England.'

Varun Jain | ETRetail | May 23, 2017, 16:29 IST

Newsletter

Share | Share | Tweet

ADITYA BIRLA GROUP

New Delhi: Aditya Birla Fashion and Retail (ABFRL) and Khadi and Village Industries Commission (KVIC)...

Government of India today announc... collaboration to produce a range of... strengthen its popularity among the...

Subscribe ETRetail Newsletter
200000+ Industry Leaders already read it
Your Email
Join Now!

Most Read | This Week | This Month

Abu Dhabi Mall offered 30min 'Free Sale' and people lost
The 30 minute sale...

Stay updated with the latest news in the Retail sector with our daily newsletter
200000+ Industry Leaders already read it everyday

Printed From
the pioneer

ADITYA BIRLA FASHION PARTNERS KVIC, TO SELL KHADI PRODUCTS

Wednesday, 24 May 2017 | PTI | New Delhi

Rate : 0/5 Like : 0

Aditya Birla Fashion and Retail on Tuesday said it has tied up with the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and launched a product line 'Khadi by Peter England'. Peter England is a menswear brand from the fashion brands portfolio of Aditya Birla Fashion and Retail Ltd (ABFRL).

As part of the collaboration, Peter England will develop an exclusive product line branded as 'Khadi by Peter England', the company said in a statement. Under the partnership, Peter England has agreed for a guaranteed minimum procurement of Khadi and Khadi products for a period of five years with primary purchases of muslin cotton and silk. Commenting on the development, ABFRL Business Head Ashish Dikshit said: "Through our partnership with KVIC, we aim to bring the rich Indian heritage of hand-woven fabric closer to our discerning consumers." The company said the new label will be available at around 700 Peter England stores and KVIC outlets besides leading ecommerce portals. It further said KVIC has permitted ABFRL to promote the sale and marketing of Khadi or products of village industries or handicrafts and forge links with established marketing agencies through the PPP mode. Peter England will procure all India Khadi varieties from departmental sales outlets of KVIC for OTC sales as well as crafting garments for its apparel brands.

Additionally, Khadi logo will be displayed across Peter England stores through visual merchandising, where Khadi products are displayed, the company said. Currently, Khadi is being marketed by Khadi Gramodyog Bhavan's stores as well as through the sales outlets run by the institutions financed by KVIC and KVIB.

न्यूज

6/6/2017 Marketing convergence between Khadi and Village Industries Commission, | Latest News & Updates at Daily News & Analysis

Marketing convergence between Khadi and Village Industries Commission,

Ministry of MSME, Government of India and Aditya Birla Fashion and Retail Ltd

New Delhi [India], May 23 (ANI-NewsVoir): Adding a new strength to Khadi India?s fashion power-house, Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. and Khadi and Village Industries Commission, Ministry of MSME, Government of India today announced a strategic collaboration to strengthen the synergies between the two iconic Indian brands.

This initiative is in line with the Hon. Prime Minister?s vision of promoting ?Khadi for Fashion? and hand-woven fabric. The agreement document was exchanged between Ms. Anshu Sinha, CEO, KVIC and Mr. Ashish Dikshit, Business Head, Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. in the august presence of Shri Vinai Kumar Saxena, Chairman KVIC and other dignitaries.

---

live mint

Print Close

Wed, May 24 2017. 01 22 AM IST

Peter England to launch khadi line

The collection named 'Khadi by Peter England' will be launched in the metros, starting October 2017

Currently, Peter England operates 700 exclusive brand outlets in India and around 15 stores outside the country.

New Delhi: Aditya Birla Fashion and Retail Ltd (ABFRL), formerly known as Pantaloons Fashion, on Tuesday partnered with Khadi and Village Industries Commission (KVIC), ministry of micro, small and medium enterprises (MSME) for a period of five years, to launch a new line of Khadi products under the brand Peter England.

The menswear brand from Madura Fashion and Lifestyle, a unit of Aditya Birla Fashion and Retail Ltd (ABFRL) is the latest to partner with KVIC, after textile and apparel maker Raymond announced the launch of its Khadi label—Khadi by Raymond on Monday. Apart from Peter England, Madura Fashion and Lifestyle has brands like Louis Philippe, Van Heusen and Pantaloons in its portfolio.

"It is a big step for sustainable fashion which is our objective. Consumers understand the ethnicity and nationalism of Khadi. So far, the availability of Khadi and Khadi products in the branded space has been limited. That's the bridge we are trying to cross," said Ashish Dikshit, business head at ABFRL.

The collection named 'Khadi by Peter England' will be launched in the metros, starting October 2017. The garments will be priced between Rs1,000 and Rs3,000, which is the regular price range of Peter England. Going forward, ABFRL is also looking to introduce Khadi range of products under other brands (depending on the cost-benefit analysis) from its portfolio.

Last year, the brand had also partnered with India Handloom Brand (a government initiative to promote high quality handloom products) and collaborated with handloom weavers from Andhra Pradesh to develop an exclusive line of shirts. Currently, Peter England operates 700 exclusive brand outlets in India and around 15 stores outside the country.

"With this convergence, over 2 lakh man hours will be generated which will benefit our artisans to a great extent. The KVIC - Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. convergence is a major initiative to bring Khadi into the branded garments market in a big way with better designs, colours, and style to cater to the youth segment and the high end market," said V.K. Saxena, chairman at the state-run KVIC.

This partnership comes after KVIC, in 2016, had sent notices to a few apparel companies including Madura Fashion and Lifestyle over unauthorized use of the word 'Khadi', following which most of the companies had stopped the production under their Khadi labels and revised their existing collections.

According to the Khadi Mark Regulations of 2013, notified by the ministry of micro, small and medium enterprises, brands that put out khadi products or garments have to apply for a Khadimark Regulation Certificate. No product can be sold as khadi without the Khadi mark tag, according to the regulation.

Earlier in February, KVIC had also sent a legal notice to garment retail chain Fabindia for continuing to sell garments in the name of khadi.

For the quarter ended March, ABFRL reported a net profit of Rs21.83 crore on standalone basis, up from a net loss of Rs108.97 crore in the year ago period. The company had reported a standalone net profit of Rs53.50 crore for the entire year 2016-17, compared with a net loss of Rs109.75 crore in 2015-16.

BUREAUCRACY Today (http://www.bureaucracytoday.com/index1.aspx)

hindustantimes

Content Sharing with HT

(http://www.hindustantimes.com)

MDI Post Graduate Programme in Public Policy & Management PGP-PPM 11th Batch · Beginning April, 2017 · Last date for applying Friday, April 14, 2017 · Apply Now

(http://www.mdi.ac.in/)

CORPORATE WORLD

Peter England to produce Khadi garments

Dipak Pradhan, New Delhi
24/05/2017 (Mailto:info@bureaucracytoday.com) 0 Comments

UK's leading clothing brand, Peter England, has been chosen to develop an exclusive product line branded as "Khadi by Peter England".

The initiative is part of the alliance reached between Aditya Birla Fashion and Khadi Village Industries Commission, in line with Prime Minister Narendra Modi's vision of promoting "Khadi for Fashion".

The KVIC, a statutory body established by an Act of Parliament, permits sale and marketing of Khadi, a hand-woven fabric or products of Village industries or handicrafts, and forge links with established marketing agencies through the PPP mode.

Under this convergence, Peter England has agreed for a guaranteed minimum procurement of Khadi and Khadi products for a period of five years with primary purchases of muslin cotton and silk.

The "Khadi by Peter England" will be made available at all the Peter England stores spread across the country, including KVIC outlets and leading ecommerce portals, Aditya Birla Fashion has said in an official statement.

Currently, there are around 700 retail points selling Peter England brand which will be i... added.

The convergence is also expected to provide around 2 lakhs man hours to the Khadi artis...

The KVIC, on the other hand, said to have received bulk orders from other corporate... Health, JK Cement etc., to develop the market for Khadi.

6/6/2017 Mahatma's fabric dons a fashion avatar — 'Khadi by Peter England' | Business Line

THE HINDU BusinessLine

Mahatma's fabric dons a fashion avatar — 'Khadi by Peter England'

Our Bureau
New Delhi, May 23:

Khadi, the hand-spun iconic fabric associated with India's freedom movement, discovered and promoted Mahatma Gandhi, will soon be available in a new avatar – "Khadi by Peter England'.

To give a fashion push to the fabric, Aditya Birla Fashion and Retail and Khadi and Village Industries Commission (KVIC), Ministry of Medium, Small and Micro Enterprises (MSME) on Tuesday announced a strategic collaboration to strengthen the synergies between the two Indian brands.

As a part of the strategic partnership, Peter England, a well-known menswear brand from the portfolio of Aditya Birla Fashion, will develop an exclusive product line branded 'Khadi by Peter England', a company release said.

Under this convergence, Peter England has agreed for a guaranteed minimum procurement of Khadi and Khadi products for five years with primary purchases of muslin cotton and silk. Peter England will also bring in the design interventions at Khadi manufacturing clusters along with providing technical expertise, the release added.

'Khadi by Peter England' will be available at Peter England stores across the country, KVIC outlets and leading ecommerce portals.

KVIC Chairman VK Saxena, claimed the convergence will provide around two lakh manhours to Khadi artisans and will bring in the "much-needed professional input in Khadi readymades."

On the marketing initiatives, Anshu Sinha, CEO, KVIC, said: "KVIC has developed convergence with major market leaders, such as like Raymond and Aditya Birla Fashion and Retail. This will be a win-win proposition for both the organisations and will bring in sustainable employment to Khadi artisans."